



पेज 05

खड़गे के बयान से
मचा हंगामा

साप्ताहिक

शहर सत्ता

PRGI NO. CTHIN/25/A2378

सोमवार, 26 अक्टूबर से 01 नवंबर 2026

हम दिखाएंगे आईना...



पेज 08

स्मृति ईरानी ने दिया कार्यकर्ताओं
को अनुशासन का संदेश

वर्ष : 02 अंक : 34 पृष्ठ : 08 मूल्य : 5 रुपए

www.shaharsatta.com



पेज

04

खुरचन : अर्थशास्त्र का नया सिद्धांत : माल में दम न हो, तो दाम बढ़ा दो!

‘सशक्त नारी-युवा उड़ान’ थीम पर होगा राज्योत्सव 2026

नवा रायपुर में 1 से 3 नवंबर तक आयोजन



मुख्य संवाददाता/प्रदीप चंद्रवंशी
मोबाईल नंबर 7000681023



छत्तीसगढ़ अपने 26वें स्थापना दिवस के जश्न के लिए पूरी तरह तैयार है। नवा रायपुर के तूता मेला मैदान में 1 नवंबर से 3 नवंबर 2026 तक तीन दिवसीय भव्य ‘छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2026’ का आयोजन किया जाएगा। इस बार के राज्योत्सव में केंद्रीय मंत्रियों के दौरे से लेकर भारतीय वायुसेना के एयर शो और बॉलीवुड कलाकारों के धमाकेदार परफॉर्मेंस तक कई बड़े आकर्षण देखने को मिलेंगे। राज्योत्सव पर राजधानी समेत राज्यभर के लोगों को एयर शो देखने को मिलेगा। पिछली बार सूर्य किरण टीम ने फाइटर जेट के साथ रोमांचक और हैरतअंगेज स्टंट दिखाए थे। इस बार वायु सेना की सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम भारत में ही बने नौ स्वदेशी ध्रुव हेलीकॉप्टरों के साथ हैरतअंगेज एयरोबेटिक शो करेगी। 1 नवंबर से शुरू होने वाले राज्योत्सव में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया शामिल होंगे। हालांकि दोनों ही नेता राज्योत्सव के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे या समापन में यह अभी तक तय नहीं है।

अमित शाह और मनसुख मांडविया होंगे शामिल

रायपुर। छत्तीसगढ़ अपने 26वें स्थापना दिवस के जश्न के लिए पूरी तरह तैयार है। नवा रायपुर के तूता मेला मैदान में 1 नवंबर से 3 नवंबर 2026 तक तीन दिवसीय भव्य ‘छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2026’ का आयोजन किया जाएगा। इस बार के राज्योत्सव में केंद्रीय मंत्रियों के दौरे से लेकर भारतीय वायुसेना के एयर शो और बॉलीवुड कलाकारों के धमाकेदार परफॉर्मेंस तक कई बड़े आकर्षण देखने को मिलेंगे। राज्योत्सव पर राजधानी समेत राज्यभर के लोगों को एयर शो देखने को मिलेगा। पिछली बार सूर्य किरण टीम ने फाइटर जेट के साथ रोमांचक और हैरतअंगेज स्टंट दिखाए थे। इस बार वायु सेना की सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम भारत में ही बने नौ स्वदेशी ध्रुव हेलीकॉप्टरों के साथ हैरतअंगेज एयरोबेटिक शो करेगी। 1 नवंबर से शुरू होने वाले राज्योत्सव में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया शामिल होंगे। हालांकि दोनों ही नेता राज्योत्सव के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे या समापन में यह अभी तक तय नहीं है।



इस बार की थीम: ‘सशक्त नारी-युवा उड़ान’

इस बार के राज्योत्सव की थीम ‘सशक्त नारी-युवा उड़ान’ तय की गई है, जो पूरी तरह से महिला सशक्तीकरण और युवाओं की भागीदारी पर केंद्रित है। आयोजन स्थल पर विभिन्न विभागों द्वारा भव्य प्रदर्शनियां और स्टॉल लगाए जाएंगे, जिनमें ईज ऑफ़ इंडिंग बिजनेस मानव पूंजी विकास और विकसित भारत और अंजोर छत्तीसगढ़ को प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा।

बॉलीवुड सिंगर्स का जलवा और लोक संस्कृति की झलक

सांस्कृतिक कार्यक्रमों में दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए देश के जाने-माने कलाकार पहुंच रहे हैं। तीन दिवसीय इस महोत्सव में प्रसिद्ध बॉलीवुड सिंगर पलक मुच्छल, स्वस्ति मेहुल और अभिजीत भट्टाचार्य अपनी सुरीली आवाज का जादू बिखेरेंगे। इसके अलावा, छत्तीसगढ़ के स्थानीय कलाकार राज्य की पारंपरिक लोक संस्कृति की जीवंत झलक पेश करेंगे। नक्शेदेखें

रूट, पार्किंग और सुरक्षा के कड़े इंतजाम

लाखों की संख्या में पहुंचने वाले दर्शकों की सुविधा के लिए जिला प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। आयोजन स्थल तक पहुंचने के लिए 6 रूट तय किए गए हैं। अलग-अलग शहरों से आने वाले वाहनों के लिए बड़ी पार्किंग बनाई गई है, जहां से दर्शक पैदल स्थल तक पहुंचेंगे (कुल 40 हजार वाहनों की पार्किंग क्षमता)।

स्थल पर 20 बेड का अस्पताल, ICU, 25 एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तैनात रहेंगी। मुख्य मंच के सामने विशाल डोम बनाए गए हैं जिनमें 60 LED स्क्रीन लगाई जा रही हैं, साथ ही 300 से अधिक शौचालयों की व्यवस्था की गई है।



राज्य अलंकरण समारोह

राज्योत्सव के अंतिम दिन यानी 3 नवंबर को भव्य राज्य अलंकरण समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय और उत्कृष्ट कार्य करने वाली प्रदेश की चुनिंदा हस्तियों को कुल 40 राज्य स्तरीय अलंकरण एवं पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।



किसानों के हित में 27 को अन्नदाता गर्जना रैली

शहर सत्ता/रायपुर।किसानों की विभिन्न समस्याओं और लंबित मांगों को लेकर भारतीय किसान संघ, छत्तीसगढ़ ने 27 अक्टूबर को नया रायपुर में ‘अन्नदाता गर्जना रैली’ का आह्वान किया है।रैली सुबह 11 बजे होगी। इसके बाद महानदी भवन घेराव प्रस्तावित है। इसमें प्रदेश के सभी जिलों से बड़ी संख्या में अन्नदाताओं के शामिल होने की संभावना है। रैली के माध्यम से संगठन किसानों की 10 सूत्रीय मांगों को शासन के समक्ष रखकर उनके निराकरण की मांग करेगा। आंदोलन के प्रमुख मुद्दों में धान खरीदी का उचित मूल्य, लंबित भुगतान, फसल क्षतिपूर्ति और सिंचाई सुविधाओं का विस्तार शामिल हैं।संघ की मांग है कि धान खरीदी की दर 3 हजार 358 रुपए प्रति क्विंटल करने, वर्ष 2022-23 की धान खरीदी से संबंधित 1,700 करोड़ रुपए के लंबित भुगतान का तत्काल निराकरण किया जाए। भारतीय किसान संघ धान खरीदी की अवधि 15 नवंबर से 15 फरवरी तक निर्धारित करने और तैल संबंधी नियमों को स्पष्ट करने की मांग भी उठाएगा। संगठन टोकन व्यवस्था में सुधार के साथ बड़े, लघु और सीमांत किसानों को उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप टोकन उपलब्ध कराने की मांग कर रहा है।रैली में बाद प्रभावित किसानों की फसलों का सर्वेक्षण कर उचित मुआवजा देने, अरपा-भैंसाझार सहित अधूरी सिंचाई परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने तथा नई सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति देने की मांग उठाई जाएगी। इसके अलावा खाद की निर्धारित कीमत से अधिक पर बिक्री रोकने और नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग भी शामिल है। संघ की मांगों में गौ संरक्षण एवं संवर्धन को बढ़ावा देना, कृषि विविधीकरण को प्रोत्साहित करना तथा मक्का और गेहूँ की समर्थन मूल्य पर खरीदी सुनिश्चित करना भी शामिल है। भारतीय किसान संघ ने किसानों से 27 अक्टूबर को नया रायपुर पहुंचकर ‘अन्नदाता गर्जना रैली’ में शामिल होने का आह्वान किया है। प्रस्तावित रैली और महानदी भवन घेराव के जरिए संगठन किसान हितों से जुड़े मुद्दों पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए मांगों के निराकरण के लिए दबाव बनाएगा।

बिलाईगढ़ में कांग्रेस ने प्रदर्शन कर पुतला जलाया

शहर सत्ता/बिलाईगढ़। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बिलाईगढ़ के अध्यक्ष लकेश्वर देवांगन के नेतृत्व में ‘वोट चोर गद्दी छोड़’ अभियान के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के विरोध में प्रदर्शन किया गया। इस दौरान पुतला दहन कर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने की मांग की। कार्यकर्ताओं ने कहा कि लोकतंत्र में प्रत्येक मतदाता का वोट महत्वपूर्ण है। चुनाव व्यवस्था में जनता का विश्वास बनाए रखने और मतदाताओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए निष्पक्ष चुनाव जरूरी हैं।प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी भी की। कार्यक्रम में विधायक कविता प्राण लहरे सहित कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए।विधायक प्रतिनिधि शेखर भट्ट,रामनारायण भट्ट, रामा हिरवानी सहित अन्य उपस्थित रहे।

भिलाई इस्पात संयंत्र की बिक्री को लेकर कांग्रेस का दुष्प्रचार शर्मनाक

शहर सत्ता/रायपुर। भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा सांसद लक्ष्मी वर्मा ने भिलाई इस्पात संयंत्र की बिक्री को लेकर कांग्रेस नेताओं द्वारा फैलाए जा रहे दुष्प्रचार पर कड़ा एतराज जताते हुए भिलाई स्टील प्लांट को निजी हाथों अथवा अड़ानी समूह को बेचे जाने की बातों को पूरी तरह मनगढ़ंत, भ्रामक और सफेद झूठ बताया है। यदि कांग्रेस नेताओं में जरा भी सच्चाई है, तो वे अनर्गल प्रलाप करने के बजाय जनता के सामने इसके ठोस तथ्य और प्रमाण पेश करें अन्यथा अपने इस सफेद झूठ के लिए बिना शर्त माफी मांगें। भाजपा सांसद श्रीमती वर्मा ने कहा कि भिलाई स्टील प्लांट केवल एक औद्योगिक प्रतिष्ठान नहीं, बल्कि भिलाई सहित समूचे छत्तीसगढ़ के मान-सम्मान, अस्मिता और लाखों श्रमिकों के पसीने की पहचान है। जब भी कांग्रेस राजनीतिक रूप से अप्रासंगिक होती है, वह जनता में भय और भ्रम फैलाने का षड्यंत्र रचने लगती है। जनाधार खो चुके भूपेश बघेल और देवेंद्र यादव जैसे कांग्रेस नेता आज हाताश और कुण्ठा में इस कदर घिर चुके हैं कि वे राज्य के गौरव से जुड़े संयंत्र को लेकर भी खुलेआम अफवाहें फैलाने का शर्मनाक कृत्य कर रहे हैं। श्रीमती वर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार बीएनपी के आधुनिकीकरण, क्षमता विस्तार और इसे नई ऊँचाइयों पर ले जाएगी।

कांग्रेस हर अच्छे काम में निकालती है खोट : उप मुख्यमंत्री अरुण साव

राष्ट्रपति के सम्मान कार्यक्रम पर कांग्रेस की नकारात्मक राजनीति

शहर सत्ता/रायपुर। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि, कांग्रेस को किसी भी अच्छे काम में अच्छाई दिखाई नहीं देती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सेवा सम्मान पर्व में स्तंदान करने वाली छत्तीसगढ़ की 11 हजार से अधिक महिलाओं का सम्मान किया। लेकिन माताओं का यह सम्मान उनसे देखा नहीं जा रहा है। उन्होंने युवा प्रबोधन में राज्य के युवाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। इस पर भी उन्हें दर्द हो रहा है। श्री साव ने कहा कि राष्ट्रपति ने पूज्य माता साहिब हासी देवी की 200वीं जयंती पर 200 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया। विश्वप्रसिद्ध बस्तर दशहरा में शामिल हुई। कांग्रेस को यह सब भी अच्छा नहीं लग रहा है। यह उसकी नकारात्मक मानसिकता को दर्शाता है।

श्री साव ने कहा कि कांग्रेस आज भी ऐसे मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रही है, जिनसे आम लोगों का कोई सरोकार नहीं है। जिस नेतृत्व में कांग्रेस 100 चुनाव हार चुकी है, उसके बावजूद कांग्रेस अपनी रणनीति बदलने को तैयार नहीं है। ईवीएम, चुनाव आयोग और एसआईआर जैसे विषयों पर बार-बार सवाल उठाकर जनता को भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि



कांग्रेस का पूरा ध्यान राहुल गांधी को लांच करने पर है। जब प्रोडक्ट ही खराब है तो वह कभी लांच हो नहीं सकता है, इसलिए बार बार वह फेल होगे।

उप मुख्यमंत्री साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस को सत्ता का अवसर दिया था, लेकिन पार्टी ने प्रदेश को अपराध, भ्रष्टाचार और नशे की समस्या से घेर दिया। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में भ्रष्टाचार बढ़ा, विकास कार्य प्रभावित हुए और प्रदेश की संस्थाओं को नुकसान पहुंचा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने जनता के

विश्वास का दुरुपयोग किया और प्रदेश के संसाधनों की लूट की। छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस की सरकारों के कामकाज को देखा और उनके परिणाम भी भुगतें हैं। श्री साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता अब कांग्रेस की सच्चाई जान चुकी है। प्रदेशवासी विकास, सुशासन और जनकल्याण के पक्ष में हैं। कांग्रेस के झूठे वादों और भ्रामक प्रचार से जनता दोबारा गुमराह होने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास न सकारात्मक सोच है और न ही जनहित का कोई ठोस एजेंडा है। इसलिए छत्तीसगढ़ में इनकी दाल कभी नहीं गलेगी। आने वाले 25 सालों तक राज्य में कांग्रेस के आने की कोई दूर दूर तक संभावना नहीं है।

कांग्रेस और विपक्ष कर रहे हैं वोट चोरी का झूठा नैरेटिव गढ़ने की कोशिश : संतोष पाण्डेय

शहर सत्ता/रायपुर। रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता एवं सांसद संतोष पाण्डेय ने कांग्रेस सहित विपक्षी दलों पर कड़ा प्रहार करते हुए आरोप लगाया है कि विपक्षी दल निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया को नुकसान पहुंचाने और जनता को भ्रमित करने का निरन्तर प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हो रहे विकास कार्यों से ध्यान भटकाने के लिए विपक्ष अब निर्वाचन आयोग और चुनाव प्रणाली पर बेबुनियाद सवाल खड़े कर रहा है। श्री पाण्डेय शनिवार को यहाँ कुशाभाऊ ठाकरे परिसर स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में पत्रकार वार्ता को सम्बोधित कर रहे थे।

भाजपा मुख्य प्रदेश प्रवक्ता श्री पाण्डेय ने चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ी से कांग्रेस का पुराना इतिहास खंगालते हुए बताया कि 1952 के चुनाव में कांग्रेस ने कम्युनिस्टों के साथ मिलकर बाबासाहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर को हराने की साजिश रची थी। 1957 में बिहार के बेगूसराय में देश के पहले बूथ पर कांग्रेस समर्थकों द्वारा कब्जा करने की घटना हुई थी। 1967 में जम्मू-कश्मीर में कांग्रेस ने प्रतिद्वंदियों को चुनाव से



रोककर निर्विरोध 61 सीटें जीती थीं। श्री पाण्डेय ने सन 1975 के घटनाक्रम की चर्चा करते हुए कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के तत्कालीन न्यायमूर्ति जगमोहन लाल सिन्हा ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का दोषी पाते हुए 6 वर्षों के लिए किसी भी सार्वजनिक पद के अयोग्य घोषित कर दिया था। 1987 का कश्मीर चुनाव कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बड़े पैमाने पर धांधली कर जीता था। इसके अलावा देश में कई चुनी हुई सरकारों को कांग्रेस ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए बर्खास्त किया। भाजपा मुख्य प्रदेश प्रवक्ता श्री पाण्डेय ने घटते जनाधार से बौखलाकर लगाए जा रहे वोट चोरी के आरोपों के परिप्रेक्ष्य में कहा कि 1952 में कांग्रेस का वोट शेयर 45% था, जो 2024 के लोकसभा चुनाव में गिरकर महज 21.4% रह गया है। जनता का समर्थन खो चुकी कांग्रेस के पास कोई ठोस एजेंडा नहीं बचा है, इसलिए वह

हार के डर से वोट चोरी और ईवीएम जैसे झूठे बहाने बना रही है। श्री पाण्डेय ने राहुल गांधी द्वारा विदेश (अमेरिका) में जाकर भारतीय निर्वाचन आयोग के खिलाफ झूठे बयान देने की भी कड़ी आलोचना की।

26 अक्टूबर को ABVP निकालेगी विद्यार्थी हुंकार रैली सप्रे स्कूल ग्राउंड से महिला थाना चौक तक निकलेगी रैली

शहर सत्ता/रायपुर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) रायपुर महानगर की ओर से 26 अक्टूबर को ‘अराजकता रोको–लोकतंत्र अपनाओ’ अभियान के तहत विद्यार्थी हुंकार रैली निकाली जाएगी। रैली दोपहर 12:45 बजे सप्रे स्कूल वॉलीबॉल ग्राउंड से शुरू होकर महिला थाना चौक स्थित जनसंपर्क कार्यालय के सामने तक जाएगी। इसके बाद खुले मंच का आयोजन किया जाएगा। अभाविप के मुताबिक, रैली का उद्देश्य लोकतांत्रिक मूल्यों, संविधान के नियमों और शांतिपूर्ण विरोध के महत्व को बताना है। संगठन का कहना है कि लोकतंत्र में मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन भ्रामक प्रचार, अपमानजनक भाषा और धमकी जैसी गतिविधियां लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ हैं। संगठन ने



बताया कि रैली में SAR के नाम पर लोगों को भ्रमित करने के कथित प्रयास, संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के खिलाफ अपमानजनक भाषा के इस्तेमाल और संवैधानिक संस्थाओं के प्रति नकारात्मक माहौल बनाने जैसे मुद्दों का विरोध किया जाएगा। इसके साथ ही देश के हालात की तुलना बांग्लादेश और नेपाल से करने संबंधी बयानों पर भी विरोध जताया जाएगा। रैली में अभाविप की पूर्व राष्ट्रीय मंत्री और वर्तमान केंद्रीय कार्यसमिति सदस्य शालिनी वर्मा और प्रदेश मंत्री अनंत सोनी शामिल होंगे। रैली के बाद महिला थाना चौक पर खुले मंच में वक्ता लोकतांत्रिक मूल्यों, संवैधानिक मर्यादाओं और शांतिपूर्ण विरोध के महत्व पर अपने विचार रखेंगे। त दोहन जारी है।

छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से 31 जनवरी तक धान खरीदी

शहर सत्ता/रायपुर। छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर 2026 से धान खरीदी की शुरुआत होने जा रही है। सरकार 3100 रुपए समर्थन मूल्य पर किसानों से धान खरीदेगी।पंजीकृत किसानों से 1 एकड़ में अधिकतम 21 क्विंटल धान लिया जाएगा। धान खरीदी का यह अभियान 31 जनवरी 2027 तक चलेगा। दुर्गा पंडवानी महासम्मेलन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने तारीख का ऑफिशियल ऐलान किया। राज्य सरकार ने इस सीजन में कुल 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का बड़ा लक्ष्य रखा है। पिछले साल 140 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया था। धान खरीदी का लक्ष्य इस साल 20 लाख मीट्रिक टन बढ़ा है।

पिछले 5 सालों में 63% बढ़ा धान खरीदी का लक्ष्य

2021-22: 98 लाख मीट्रिक टन
2026-27: 160 लाख मीट्रिक टन
5 साल में लक्ष्य 1.63 गुना बढ़ा
कुल बढ़ोतरी: 62 लाख मीट्रिक टन (करीब 63%)

मोहम्मद अकबर बोले-छत्तीसगढ़ में SAR से 25 लाख वोटर कटे

फॉर्म-7 के जरिए नाम काटने की प्रक्रिया में जांच की मांग की

शहर सत्ता/रायपुर। छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची से करीब 25 लाख नाम कम होने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर ने निर्वाचन आयोग से जवाब मांगा है। 2023 के बाद आबादी बढ़ने के बावजूद राज्य में मतदाताओं की संख्या कैसे घट गई? उन्होंने विशेष गहन पुनरीक्षण (SAR) के दौरान फॉर्म-7 के इस्तेमाल और इसके आधार पर नाम काटने की प्रक्रिया की जांच कराने की मांग की है।

मोहम्मद अकबर ने दस्तावेजों के आधार पर दावा किया कि राज्य में 2023 से अब तक 24 लाख 99 हजार मतदाता कम हुए हैं। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग को बताना चाहिए कि मतदाता सूची से हटाए गए नामों में कितने मामले फॉर्म-7 के आधार पर थे और उन्में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया या नहीं।

रायपुर में सबसे ज्यादा 31 हजार नाम कटे

अकबर के मुताबिक, छत्तीसगढ़ के 33 जिलों में कुल 1 लाख 8 हजार 807 मतदाताओं के नाम काटे गए हैं। इनमें रायपुर में 31,028, कोरबा में 15,187, दुर्ग में 7,209, बालोद में 3,903, बलौदाबाजार-भाटापारा में 2,662 और कबीरधाम में 2,234 नाम शामिल हैं। उन्होंने निर्वाचन आयोग से पूछा कि इन नामों में कितने फॉर्म-7 के आधार पर हटाए गए। क्या आपति दर्ज कराने वाले लोगों के बयान लिए गए और जिन मतदाताओं के नाम काटने की मांग की गई, उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया?



गलत जानकारी देकर नाम कटवाने पर कार्रवाई का प्रावधान

मोहम्मद अकबर ने कहा कि फॉर्म-7 दाखिल होने भर से किसी मतदाता का नाम सूची से नहीं कट जाता। आपति पर कार्रवाई से पहले संबंधित पक्षों को सुनना और अधिकारी का आपति की वैधता से संतुष्ट होना जरूरी है। उन्होंने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 का हवाला देते हुए कहा कि जानबूझकर गलत जानकारी या घोषणा देकर मतदाता सूची से नाम कटवाने की कोशिश करने पर एक साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। अकबर ने आयोग से यह भी पूछा कि कितनी शिकायतें झूठी पाई

गई और ऐसे मामलों में कितने शिकायतकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की गई।

चुनावी जीत-हार के अंतर से की तुलना

कांग्रेस नेता ने कहा कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस और भाजपा के बीच जीत-हार का अंतर 6 लाख 32 हजार वोटों का रहा, जबकि उनके दावे के मुताबिक, 2023 से अब तक मतदाताओं की संख्या में करीब 25 लाख की कमी आई है। उन्होंने इस अंतर को लेकर निर्वाचन आयोग से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की। अकबर ने कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए जरूरी है कि मतदाता सूची से नाम हटाने की प्रक्रिया पारदर्शी हो। उन्होंने मांग की कि जिन मतदाताओं के नाम गलत तरीके से हटाए गए हैं, उन्हें दोबारा जोड़ा जाए और किसी भी पात्र मतदाता को वोट देने के अधिकार से वंचित न किया जाए।

वोट चोरी एक व्यापक मुद्दा है, एसआईआर समस्या का केवल एक हिस्सा : चंदन कश्यप

शहर सत्ता/रायपुर। जगदलपुर।

आज राजीव भवन जगदलपुर में “वोट बचाओ देश बचाओ” अभियान के तहत नारायणपुर के पूर्व विधायक चंदन कश्यप और कोंडागांव के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष देवचंद मतलम ने प्रेसवार्ता ली। चंदन कश्यप ने कहा कि वोट चोरी का मुद्दा केवल मौजूदा एसआईआर प्रक्रिया तक सीमित नहीं है। कांग्रेस ने कई चुनावों के दौरान मतदाता सूचियों में नाम जोड़ने और हटाने, दोहरे पंजीकरण, चुनाव संबंधी आँकड़ों में पारदर्शिता, ईवीएम और वीवीपैट की कार्यप्रणाली तथा चुनाव आयोग के आचरण पर लगातार सवाल उठाए हैं। मूल सवाल यह है कि क्या प्रत्येक पात्र नागरिक अपने संवैधानिक मताधिकार का प्रयोग कर सकता है और क्या चुनाव एक निष्पक्ष संस्था की निगरानी में कराए जा रहे हैं।

चंदन कश्यप ने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस ने अनियमितताओं पर सवाल उठाने के लिए बार-बार निर्वाचन क्षेत्र के स्तर के आंकड़े और चुनावी तुलनाएं सार्वजनिक की हैं। इसमें 7 फरवरी 2025 को महाराष्ट्र में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस, 7 अगस्त 2025 को महादेवपुरा से जुड़े आंकड़ों की प्रस्तुति, सितंबर 2025 में



आलंद से जुड़े आरोप, नवंबर 2025 में हरियाणा से जुड़े आरोप और सितंबर 2026 में चुनाव आयोग के भीतर मतभेदों के खुलासे के बाद उठाए गए नए सवाल शामिल हैं। इन प्रयासों को एसआईआर से शुरू हुआ मुद्दा नहीं, बल्कि आंकड़ों, सार्वजनिक जांच-पड़ताल और संस्थागत जवाबदेही के माध्यम से जवाब मांगने की एक निरंतर कोशिश के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। 17 फरवरी 2025 की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने 2024 के लोकसभा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के बीच लगभग 39 लाख मतदाताओं के जुड़ने पर सवाल उठाए। इसके मुकाबले, पिछले पांच वर्षों में लगभग 32 लाख मतदाता जुड़े थे। कांग्रेस ने मांग की कि बताया जाए कि ये अतिरिक्त मतदाता कौन थे, उनका पंजीकरण कब हुआ और इतने कम समय में संख्या में इतनी तेज वृद्धि क्यों हुई।





गाली देने से मना करने पर युवक को मारा चाकू

शहर सत्ता/रायपुर। रायपुर के भाटागांव में गाली-गलौज से मना करने पर एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया गया। उसकी दाहिनी जांघ और घुटने के नीचे चोटें आईं। यह घटना 23 अक्टूबर को सुबह करीब 1:30 बजे चिरीपारा में दंतेश्वरी मंदिर के पास हुई। इस मामले में पुरानी बस्ती पुलिस ने आरोपी रवि ध्रुव (26) को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से वारदात में इस्तेमाल किया गया बटनदार चाकू और घटना के समय पहनी हुई शर्ट जब्त कर ली गई है। कोर्ट में पेश करने के बाद आरोपी को ज्यूडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। पुलिस के मुताबिक, पीड़ित युवक 22 अक्टूबर की रात अपने परिचितों के साथ दुर्गा विसर्जन कार्यक्रम में शामिल होने गया था। लौटने के बाद 23 अक्टूबर की रात करीब 1:30 बजे रवि ध्रुव से उसकी मुलाकात दंतेश्वरी मंदिर के पास हुई। बातचीत के दौरान आरोपी ने पीड़ित और उसके साथियों पर टिप्पणी की, जिससे विवाद शुरू हो गया। पीड़ित ने गाली-गलौज पर टिप्पणी की, जिससे विवाद शुरू हो गया। पीड़ित ने गाली-गलौज करने से मना किया तो आरोपी ने चाकू निकालकर उस पर हमला कर दिया। इससे उसके दाहिने पैर की जांघ और घुटने के नीचे चोट आई। घटना के बाद आरोपी मौके से भाग गया। घायल को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, फिर पुरानी बस्ती थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई।

एक्टिवा सवार मां-बेटी को टक्कर मारकर स्कूटर चालक फरार

शहर सत्ता/रायपुर। रायपुर में फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों ने युवक के साथ मारपीट की और बेल्ट से हमला कर उसका मोबाइल फोन -एक्टिवा की चाबी लूट ली। घटना पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र के कंकालीपारा के पास 16 अक्टूबर की है। पुलिस के मुताबिक, घटना की शिकायत मिलने के बाद टीम ने मौके का निरीक्षण किया और गवाहों से पूछताछ की। मुखबिर से मिली जानकारी के आधार पर संदेहियों की पहचान कर उनसे पूछताछ की गई। पुलिस का कहना है कि आरोपियों ने आपसी लेन-देन के विवाद में वारदात करना स्वीकार किया है। आरोपियों के कब्जे से लूटा गया मोबाइल फोन, वारदात में इस्तेमाल किया गया लाल रंग का चमड़े का बेल्ट और एक्टिवा की चाबी जब्त की गई है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान धीरेन्द्र सिंह तोमर (37), निवासी प्रिय नगर, अग्रवाल कॉलोनी, डीडी नगर और आकाश पाण्डेय (38), निवासी महोबा बाजार, राजीव नगर, आमानाका के रूप में हुई है। दोनों को 17 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया। उनके खिलाफ पुरानी बस्ती थाने में अपराध क्रमांक 545/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 309(6) में कार्रवाई की गई है। पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है।

प्रदेश में चाइनीज सामानों के ऑर्डर बंद, स्वदेशी की बढ़ी मांग

शहर सत्ता/रायपुर। इस बार दीपावली का बाजार केवल समृद्धि का पर्व नहीं, बल्कि स्वदेशी स्वाभिमान का उत्सव बनकर उभरा है। बाजारों में चाइनीज सामान की चमक पूरी तरह फीकी पड़ चुकी है और उसकी जगह लोकल कारीगरों के हुनर व स्वदेशी उत्पादों ने ले ली है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (केट), छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स और स्वदेशी जागरण मंच के अनुसार, 'मेक इन इंडिया' और 'वोकल फॉर लोकल' का असर धरातल पर साफ दिख रहा है। व्यापारियों ने अगस्त के बाद से ही चाइनीज सामानों का ऑर्डर पूरी तरह बंद कर दिया था, जिसके चलते इस बार बाजार में 70 से 90 प्रतिशत उत्पाद पूरी तरह स्वदेशी हैं। प्रदेश में 13000 करोड़ से 14500 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड कारोबार की उम्मीद है, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को अभूतपूर्व गति मिलेगी। कैट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमर पारवानी के अनुसार, जीएसटी दरों के युक्तियुक्तकरण और स्वदेशी की बढ़ती मांग ने घरेलू अर्थव्यवस्था को वास्तविक मजबूती दी है।

पनीर जांच में खाने लायक नहीं फिर भी 44 दिन तक रखने के बाद किया नष्ट



शररसत्ता/रायपुर। खाद्य विभाग ने शनिवार को 750 किलो पनीर नष्ट कराया। यह पनीर मिल्की मलाई और मलाई मैजिक ब्रांड का था। जांच में दोनों ब्रांड का पनीर खाने योग्य नहीं पाया गया था। इसके बावजूद 44 दिन तक इसे नष्ट नहीं किया गया। ओडिशा सप्लाई करने के दौरान विभाग ने पनीर की खेप पकड़ी थी। अब विभाग ने उरला स्थित फैक्ट्री में पनीर नष्ट कराया है। दोनों ब्रांड के मालिकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी भी की जा रही है। वहीं, एक दिन पहले भिलाई में छापेमारी के दौरान एक्सपायरी दूध से पनीर बनाने और गंदगी में मिठाइयां तैयार करने का मामला सामने आया था।

टीम ने यहां करीब 2,500 किलो मिठाई और 1,000 लीटर दूध नष्ट कराया था।

शहर के पास घर, फिर भी सड़क-पानी की गारंटी नहीं!

रायपुर, दुर्ग-भिलाई में 500 से ज्यादा कॉलोनियां बढ़ा रहीं परेशानी

रायपुर। छत्तीसगढ़ के शहरों का विस्तार तेजी से हो रहा है। लोग बेहतर कनेक्टिविटी और कम कीमत में घर बनाने की उम्मीद से नगर निगम की सीमा से बाहर प्लॉट खरीद रहे हैं। लेकिन कई जगह घर और कॉलोनियां बसने के बाद भी सड़क, पीने का पानी, नाली और स्ट्रीट लाइट जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर समेत दुर्ग-भिलाई, बिलासपुर और कोरबा के बाहरी इलाकों में यह समस्या लगातार बढ़ रही है। नगर निगम की सीमा से बाहर विकसित हो रहे इन क्षेत्रों को पेशी-अर्बन एरिया कहा जाता है। यहां अनियोजित विकास के कारण स्थानीय निकायों पर सुविधाएं उपलब्ध कराने का दबाव बढ़ रहा है।

नगर निगम की सीमा से बाहर बिल्डर कृषि भूमि या ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन खरीदकर कॉलोनियां विकसित कर रहे हैं। इन क्षेत्रों में जमीन और प्लॉट अपेक्षाकृत सस्ते मिलने के कारण लोग खरीदारी कर रहे हैं। लेकिन कई कॉलोनियों में विकास के लिए जरूरी सुविधाओं और व्यवस्थाओं की कमी सामने आ रही है। रायपुर के सेजबहार, कांदुल, अमलीडीह, दलदल सिवनी और विधानसभा मार्ग से जुड़े कई बाहरी इलाके तेजी से शहरी रूप ले चुके हैं। इसके बावजूद इन क्षेत्रों के कुछ हिस्से अब भी नगर निगम की सीमा में शामिल नहीं हो पाए हैं। ऐसे में बढ़ती आबादी की जरूरतों को पूरा करना स्थानीय निकायों के लिए चुनौती बन रहा है। रायपुर और दुर्ग-भिलाई के बाहरी इलाकों में नगर निकायों की सीमाओं के बाहर 500 से अधिक कॉलोनियां विकसित होने का अनुमान है। रायपुर के पेरिफेरल जोन के साथ दुर्ग-भिलाई के सीमावर्ती क्षेत्रों, कुम्हारी, अमलेश्वर, रिसाली के आगे और विधानसभा रोड के आसपास निजी बिल्डरों की



नगर निगम की सीमा के बाहर ग्राम पंचायत क्षेत्रों में जमीन के उपयोग परिवर्तन और निर्माण से जुड़े नियम शहरी क्षेत्रों से अलग हो सकते हैं। इसका फायदा उठाकर कुछ बिल्डर बिना पर्याप्त बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था किए प्लॉटिंग कर देते हैं। कई मामलों में कॉलोनी का विकास नियमानुसार नहीं होने से बाद में उसे अवैध घोषित किए जाने या नियमितीकरण में परेशानी आने की आशंका रहती है। ऐसे क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बिजली की अनियमित आपूर्ति, पीने के पानी की कमी, कच्ची सड़कों, नालियों और जलभराव जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। पेशी-अर्बन क्षेत्रों में आबादी बढ़ने के साथ ग्राम पंचायतों पर भी जिम्मेदारी बढ़ रही है। सीमित आर्थिक संसाधनों और तकनीकी सुविधाओं के कारण पंचायतों के लिए शहरी स्तर की सेवाएं उपलब्ध कराना आसान नहीं होता। सीवरेज सिस्टम, स्ट्रीट लाइट, कचरा प्रबंधन, पक्की सड़कें और नियमित जल निकासी जैसी व्यवस्थाओं के लिए पर्याप्त योजना और बजट की जरूरत होती है। वहीं, जब कॉलोनियों में सुविधाएं उपलब्ध नहीं होतीं, तो रहवासी स्थानीय निकायों और प्रशासन से व्यवस्था सुधारने की मांग करते हैं।

डॉक्टर गहवई के निलंबन पर डॉक्टर्स फेडरेशन ने उठाए सवाल



शहर सत्ता/रायपुर। रायपुर। छत्तीसगढ़ डॉक्टर्स फेडरेशन (CGDF) ने स्वास्थ्य विभाग के उप संचालक डॉ. धर्मेन्द्र कुमार गहवई के निलंबन पर सवाल उठाए हैं। 21 अक्टूबर को जारी निलंबन आदेश का विरोध करते हुए फेडरेशन ने कार्रवाई की निष्पक्ष समीक्षा की मांग की है। डॉ. गहवई ने स्वास्थ्य सेवा संचालनालय (DHS) में एडिशनल डायरेक्टर जैसे चिकित्सकीय संवर्ग के पदों पर गैर-चिकित्सकीय अधिकारियों की पदस्थापना को हाईकोर्ट में चुनौती दी है।

निलंबन के आधारों की समीक्षा की मांग

फेडरेशन ने कहा कि, निलंबन आदेश में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम 3 और 22(क) के उल्लंघन का उल्लेख है। कार्रवाई के आधारों और परिस्थितियों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। यदि कार्रवाई

प्रतिशोधात्मक या दुर्भावनापूर्ण पाई जाती है, तो निलंबन निरस्त किया जाए। CGDF ने कहा कि, न्यायालय की शरण लेना प्रत्येक चिकित्सक का अधिकार है। ऐसे में कार्रवाई की निष्पक्षता सुनिश्चित होनी चाहिए, ताकि चिकित्सक अपने वैधानिक अधिकारों के इस्तेमाल से हतोत्साहित न हों। फेडरेशन ने स्पष्ट किया कि वह उचित और नियमों के तहत होने वाली विभागीय कार्रवाई के खिलाफ नहीं है।

फेडरेशन ने स्वास्थ्य सेवा संचालनालय (DHS) के साथ चिकित्सा शिक्षा संचालनालय (D M E) में भी चिकित्सकीय संवर्ग के लिए निर्धारित पदों पर गैर-चिकित्सकीय अधिकारियों की पदस्थापना का मुद्दा उठाया है। संगठन के मुताबिक, ऐसी नियुक्तियों से चिकित्सकों के संवर्गीय अधिकारों, वरिष्ठता और पदोन्नति के अवसर प्रभावित हो सकते हैं। इससे स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता पर भी असर पड़ने की आशंका है।CGDF ने शासन से मांग की है कि दोनों संचालनालयों में विवादित पदस्थापनाओं की लागू सेवा नियमों, संवर्गीय पात्रता और वरिष्ठता के आधार पर वैधानिक समीक्षा की जाए। साथ ही, प्रशासनिक पदों पर नियुक्तियों में निर्धारित नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाए। फेडरेशन ने कहा कि वह डॉ. गहवई के निलंबन की निष्पक्ष समीक्षा, चिकित्सकीय संवर्ग के अधिकारों की रक्षा और नियमों के अनुरूप नियुक्तियां सुनिश्चित करने की मांग पर कायम है। प्रतिशोधात्मक कार्रवाई सामने आने पर संगठन न्यायिक, प्रशासनिक और लोकतांत्रिक स्तर पर विरोध करेगा।

अब रेलवे आरक्षण काउंटर से भी ले सकेंगे यात्रा बीमा

रायपुर। रेलवे में आरक्षित टिकट बुक कराने वाले यात्रियों को 27 अक्टूबर 2026 से आरक्षण काउंटरो पर भी वैकल्पिक यात्रा बीमा लेने की सुविधा मिलेगी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के सभी यात्री आरक्षण प्रणाली (PRS) काउंटरो पर यह सुविधा शुरू की जा रही है। अब तक यह विकल्प ऑनलाइन ई-टिकट बुक करते समय मिलता था। यात्री अपनी इच्छा से बीमा ले सकेंगे, यह अनिवार्य नहीं होगा।आरक्षण काउंटर पर कर्मचारी यात्रियों को बीमा की जानकारी देंगे और उनकी सहमति दर्ज करेंगे। बीमा लेने के लिए यात्री को मोबाइल नंबर देना होगा और तय प्रीमियम का भुगतान डिजिटल माध्यम से करना होगा। बीमा पॉलिसी की जानकारी पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजी जाएगी। टिकट बुक कराते समय यात्री बीमा का विकल्प चुनने से पहले इसकी शर्तें और प्रीमियम जरूर जांच लें।

मौत पर 10 लाख, इलाज के लिए 2 लाख तक बीमा

योजना के तहत पात्र रेल दुर्घटना या अन्य निर्धारित घटना में मौत होने पर 10 लाख रुपए तक का बीमा कवर मिलेगा। स्थायी रूप से पूरी तरह दिव्यांग होने पर भी 10 लाख रुपए और स्थायी आंशिक दिव्यांगता पर 7.50 लाख रुपए तक का कवर निर्धारित है।चोट लगने पर अस्पताल में भर्ती के खर्च के लिए 2 लाख रुपए तक और पार्थिव शरीर को ले जाने के लिए 10



छत्तीसगढ़ में मौसम ड्राई, 27 अक्टूबर से बारिश के आसार

शहर सत्ता/रायपुर। छत्तीसगढ़ में अगले 2 दिनों तक मौसम ड्राई रहने की संभावना है। इसके बाद 27 अक्टूबर से प्रदेश में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। मौसम विभाग के मुताबिक, 28 और 29 अक्टूबर को प्रदेश के कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने के आसार हैं। फिलहाल, प्रदेश में कहीं भी बारिश दर्ज नहीं की गई है। 24 अक्टूबर को प्रदेश में मौसम शुष्क रहा। रायपुर में अधिकतम तापमान 32.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस अंबिकापुर में रहा।राजधानी रायपुर में 25 अक्टूबर को आकाश साफ रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान जताया है।मौसम विभाग के अनुसार पूर्व-मध्य और उससे लगे दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी में बना सिस्टम 25 अक्टूबर को अवदाब में बदल सकता है। इसके बाद 26 अक्टूबर की सुबह तक चक्रवाती तूफान बनने की संभावना है। तूफान के आगे और ज्यादा तेज होने का अनुमान है। चक्रवाती तूफान 28 अक्टूबर की सुबह के आसपास आंध्र प्रदेश तट के पास पहुंच सकता है। इसके बापटला और विशाखापत्तनम के बीच आंध्र प्रदेश और यनम तट को पार करने की संभावना है। इस दौरान हवा की अधिकतम गति 115 से 125 किलोमीटर प्रति घंटा और झोंकों की गति 140 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है।



हजार रुपए तक का प्रावधान है। ये लाभ पॉलिसी की शर्तों और पात्रता के अनुसार मिलेंगे।

प्रति यात्री 45 पैसे प्रीमियम का प्रावधान

पॉलिसी दस्तावेज के अनुसार, 17 फरवरी 2024 से लागू प्रीमियम सभी कर्ों सहित 45 पैसे प्रति यात्री निर्धारित है। हालांकि, काउंटर से टिकट बुक कराते समय लागू प्रीमियम की पुष्टि करना जरूरी होगा।यह सुविधा कन्फर्म, आरएसी और आंशिक रूप से कन्फर्म टिकट वाले पात्र भारतीय रेल यात्रियों के लिए है। बिना बर्थ या सीट के यात्रा करने वाले पांच साल से कम उम्र के बच्चे इस बीमा कवर में शामिल नहीं हैं। बीमा पॉलिसी जारी करने और पात्र दावों का निपटारा करने की जिम्मेदारी संबंधित बीमा कंपनी की होगी। किसी दुर्घटना या बीमा संबंधी पूछताछ के लिए यात्रियों को पॉलिसी में दिए गए संपर्क विवरण के आधार पर सीधे बीमा कंपनी से संपर्क करना होगा।

सिटी सेंटर मॉल के पास होम डेकोरेशन दुकान में लगी आग

शररसत्ता/रायपुर। रायपुर के पंडरी में सिटी सेंटर

मॉल के पास स्थित होम डेकोरेशन की दुकान में आग लग गई। आग दुकान की चौथी मंजिल पर लगी, जहां रखा फर्नीचर जलकर राख हो गया। घटना में लाखों रुपए के नुकसान की आशंका है। घटना देवेंद्र नगर थाना क्षेत्र की है। जानकारों के मुताबिक, दुकान में आग लगने की वजह AC का कंप्रेसर फटना बताई जा रही है। हालांकि, आग लगने के वास्तविक कारण की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। आग की सूचना मिलते ही दमकल की दो गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। दमकलकर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। आग दुकान की चौथी मंजिल पर लगी, जहां रखा फर्नीचर और सजावटी सामान जलकर खाक हो गई। भीषण आग से इलाके में अफरा-तफरी का माहौल है। इधर सूचना मिलते ही मौके पर दमकल विभाग की दो गाड़ियां पहुंचीं और आग बुझाने का अभियान शुरू किया गया। अभी तक आग लगने की वजह पता नहीं चल पाया।

लाखों रुपए के नुकसान की आशंका

प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, दुकान में रखा फर्नीचर और अन्य सामान जलने से लाखों रुपये का नुकसान होने की आशंका है। हालांकि, वास्तविक नुकसान का आकलन आग बुझने और दुकान का निरीक्षण होने के बाद ही किया जा सकेगा। आग लगने की वजह



भी अभी स्पष्ट नहीं है। शॉर्ट सर्किट समेत किसी भी संभावित कारण की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। घटना में किसी के घायल होने या जनहानि की फिलहाल पुष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। आग पर नियंत्रण के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो पाएगी।

दमकल की दो गाड़ियां मौके पर

आग की सूचना पर दमकल विभाग की दो गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंचीं। दमकलकर्मी आग पर काबू पाने में जुट गए, वहीं देवेंद्र नगर थाना पुलिस भी मौके पर मौजूद रही। ऊपरी मंजिल पर आग लगने के कारण उसे बुझाने में चुनौती का सामना करना पड़ा।



संपादकीय

• सुकांत राजपूत



ग्राहकों का डेटा लीक, डिजिटल सुरक्षा पर फिर उठे सवाल

इसमें कोई दोराय नहीं कि आधुनिक तकनीक की वजह से दुनिया भर में लोगों की जिंदगी आसान हुई है और इसने बहुस्तरीय विकास को रफ्तार दी है। मगर तकनीक के अद्यतन होते जाने के साथ जैसे-जैसे इसका सार्वजनिक उपयोग एक औपचारिक व्यवस्था का रूप ले रहा है, उसी के समांतर इसके जोखिम भी सामने आ रहे हैं। भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई के हजारों ग्राहकों का डेटा डार्क वेब पर लीक हो जाने की खबर ने एक बार फिर उस जोखिम की गंभीरता और संवेदनशीलता पर विचार की जरूरत को रेखांकित किया है, जिसकी अनदेखी की जाती रही है।

गौरतलब है कि डेटा लीक की खबर आने के पहले एक हैकर गिरोह ने यह दावा किया था कि उसने एसबीआई के करीब पौने चार लाख ग्राहकों के निजी ब्योरे हासिल कर लिए हैं। इसके बाद बैंक का तंत्र सक्रिय हुआ और उसकी शुरुआती जांच में तीन हजार आठ सौ सत्तानवे ग्राहकों की निजी पहचान से जुड़ी जानकारी डार्क वेब पर मिलने की पुष्टि की गई। जाहिर है, यह साइबर संसार में लगातार खड़ी हो रही चुनौतियों की ही एक कड़ी है, जिसने यह सोचने पर मजबूर किया है कि आधुनिक तकनीक की सुविधा किस हद तक सुरक्षित है और उसके जोखिम का असर कितना गहरा हो सकता है।

एसबीआई के जिन ग्राहकों का डेटा लीक हुआ है, उसमें उनका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल, पता, आधार और कुछ अन्य ब्योरे शामिल हैं। अभी ग्राहकों के खातों पर कोई खतरा होने की बात नहीं कही गई है। हालांकि डेटा लीक होने की चेतावनी मिलने के बाद एसबीआई ने अपने सुरक्षा तंत्र को सक्रिय कर दिया, सीईआरटी-इन की एक स्वतंत्र साइबर सुरक्षा एजेंसी को जांच का जिम्मा सौंपा। मगर इस बात की क्या गारंटी है कि बैंक का अपना तंत्र जब डेटा को सुरक्षित नहीं रख सका, तो इससे इतर खतरों से वह ग्राहकों को बचा लेगा।

डार्क वेब पर होने वाली अवांछित गतिविधियां पहले ही वैश्विक स्तर पर एक गंभीर चुनौती बनी हुई थीं। अब उस संजाल में फैले गिरोहों ने जिस तरह बैंकों के डेटा तक पहुंच बनानी शुरू कर दी है, वह दुनिया भर के लिए बेहद चिंता की बात है। इसके अलावा, एक खबर यह भी आई कि भारत में डिजिटल सुरक्षा देने वाली कंपनी ई-मुद्रा में एक तकनीकी गड़बड़ी सामने आने के बाद इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इसकी जांच के लिए विशेष टीम बनाई है। इसके बाद सरकार ने सफाई दी कि इस खामी का असर कंपनी के सिर्फ विदेशी कारोबार पर पड़ा है।

सवाल है कि एसबीआई के डेटा लीक या ई-मुद्रा में तकनीकी खामी क्या यह नहीं दर्शाती कि अगर आने वाले वक्त में डार्क वेब पर मौजूद या कोई अन्य गिरोह व्यापक और जटिल धोखाधड़ी के लिए साइबर हमला करता है, तो उसका सामना करने के लिए हमारा डिजिटल तंत्र पूरी तरह तैयार नहीं है? मुश्किल यह है कि डार्क वेब यानी इंटरनेट के छिपे हुए हिस्से में जिस तरह डेटा चोरी, उसकी अवैध खरीद-बिक्री का व्यापक संजाल खड़ा हो चुका है, उससे पार पाने के लिए डिजिटल संसार में अब तक कोई सुरक्षा दीवार खड़ी नहीं की जा सकी है।

अगर साइबर अपराधियों का कोई गिरोह दुनिया के अलग-अलग देशों के बेहद अहम संस्थानों की संवेदनशील सूचनाओं तक इतनी आसानी से पहुंच बनाकर डेटा हैक कर सकता है, तो ऐसे में एक आम आदमी अपने बैंक खाते या इंटरनेट पर मौजूद अपनी अन्य निजी जानकारीयों और सामग्री के सुरक्षित होने का भरोसा कैसे करे?

संपादकीय

अर्थशास्त्र का नया सिद्धांत : माल में दम न हो, तो दाम बढ़ा दो!

छत्तीसगढ़ में नकली पनीर (एनालॉग) पर प्रतिबंध है, लेकिन बाजार में उसका खेल बंद नहीं हुआ। कानून अपनी फाइलों में रास्ता तलाशता रहता है और मिलावटखोर मुनाफे का हाईवे पकड़कर फरटि भरते हैं। गजब का कारोबार है! माल नकली, धंधा असली और मुनाफा एकदम खरा! ग्राहकों को लूटने में भी कोई मिलावट नहीं।

इन कारोबारियों ने अर्थशास्त्र का नया सिद्धांत गढ़ लिया है—माल में दम न हो, तो दाम बढ़ा दो! सस्ता बेचोगे तो ग्राहक शक करेगा, महंगा बेचोगे तो शुद्धता का प्रमाणपत्र खद ही जारी कर देगा। अब नकली पनीर को असली साबित करने के लिए दूध की जरूरत नहीं, ऊंची कीमत ही काफी है।

वाह रे बाजार! मिलावट भी तुम्हारी, कीमत भी तुम्हारी और ग्राहक की आंखों पर बंधी पट्टी भी तुम्हारी! ग्राहक सोचता है—इतना महंगा है, जरूर असली होगा। उधर मिलावटखोर मन ही मन मुस्कुराता है—वाह रे ग्राहक! तूने मेरे नकली माल को महंगा समझकर नहीं, महंगा देखकर असली मान लिया! मिलावटखोरों का अर्थशास्त्र ही निराला है—माल में मिलावट बढ़ाओ, दाम में दम बढ़ाओ; ग्राहक की जेब काटो और शुद्धता का भ्रम बेचकर ईमानदारी का तमगा भी पाओ! पहले मिलावट चीजों में होती थी, अब ग्राहक की समझ में भी मिलावट की जा रही है। पनीर में दूध हो न हो, कीमत में ईमानदारी का पूरा प्रदर्शन है। माल नकली बेचो, दाम असली वसूलो और ग्राहक को उसकी ही जेब कटने पर गुणवत्ता का भ्रम पालने दो! मिलावटखोर भी खुश और ग्राहक भी भ्रम में खुश! माल नकली, दाम असली और ग्राहक की जेब साफ।

अब सिर्फ पनीर ही नहीं, दूध से बनी हर सफेद चीज संदेह के दायरे में है, खुद दूध भी! नकली पनीर तो जगजाहिर है, कभी दूध में मिलावट की खबर आती है, कभी मावे की खेप पकड़ी जाती है, मिठाई, मखन और क्रीम की गुणवत्ता पर भी सवाल उठते हैं। पनीर सफेद है, इसका अर्थ यह नहीं कि वह शुद्ध है। दूध सफेद है, इसका अर्थ यह नहीं कि वह मानकों पर खरा उतरता है। मिठाई चमकदार है, इसका अर्थ यह नहीं कि उसकी गुणवत्ता भी चमकदार है और दुकान के बाहर बड़े अक्षरों में 'शुद्ध' लिख देने से कोई चीज शुद्ध नहीं हो जाती!

शुद्धता का प्रमाण विज्ञापन नहीं, जांच और जवाबदेही है। भरोसा दुकानदार की मुस्कान से नहीं, उसके कारोबार की पारदर्शिता से बनता है। मिलावटखोर सिर्फ दूध में कोई पदार्थ नहीं मिलाता। वह उस मां के भरोसे में मिलावट करता है, जो बच्चे के लिए पौष्टिक भोजन खरीदती है। वह उस परिवार की खुशी में मिलावट करता है, जो त्योहार पर मिठाई लाता है। वह उस व्यवस्था की साख में मिलावट करता है, जिससे नागरिक सुरक्षा की उम्मीद करता है। इसलिए मिलावट केवल व्यापार का अपराध नहीं, जनता के विश्वास पर हमला भी है।

छत्तीसगढ़ को ऐसी व्यवस्था चाहिए, जहां प्रतिबंधित या नियमविरुद्ध उत्पादों का कारोबार करना आसान न हो। जहां नकली उत्पादों को असली बताकर बेचना महंगा पड़े। जहां बार-बार अपराध करने वालों के खिलाफ कठोर और प्रभावी कार्रवाई हो। जहां जांच रिपोर्ट और कार्रवाई के परिणाम जनता के सामने आएँ। जहां उपभोक्ता की शिकायत को औपचारिकता मानकर फाइल में बंद न कर दिया जाए। क्योंकि सवाल सिर्फ पनीर का नहीं है। सवाल उस भरोसे का है, जिसके आधार पर आम आदमी अपनी



मेहनत की कमाई से भोजन खरीदता है।

खाद्य विभाग के सामने संसाधनों, कर्मचारियों, जांच सुविधाओं और कानूनी प्रक्रियाओं की चुनौतियां हो सकती हैं। नमूने लेने से लेकर प्रयोगशाला की रिपोर्ट और न्यायिक कार्रवाई तक समय लगता है। यह सब वास्तविक कठिनाइयां हैं। लेकिन मिलावटखोरों की ओर से जनता को कोई रियायत नहीं मिलती। वे यह कहकर कारोबार नहीं रोकते कि जांच प्रयोगशाला में लंबित है। वे यह सोचकर नकली माल बनाना बंद नहीं करते कि विभाग के कर्मचारी छुट्टी पर हैं। उनका कारोबार चलता रहता है। जनता की थाली सजती रहती है। और हर बार उपभोक्ता ही जोखिम उठाता है।

व्यवस्था को यह तय करना होगा कि उसकी प्राथमिकता क्या है—कार्रवाई की सूचना जारी करना या मिलावट की आपूर्ति रोकना? छापे की संख्या गिनना या दोषियों को सजा दिलाना? नमूने लेना या बाजार को सुरक्षित बनाना?

छापे की तस्वीर अखबार में छप जाती है। जब्त माल का आंकड़ा सुर्खी बन जाता है। मगर जनता को यह जानने में भी दिलचस्पी है कि उस मामले का अंतिम परिणाम क्या निकला। कितने मामलों में दोष साबित हुआ? कितनों को दंड मिला? कितने कारोबारियों ने दोबारा वही अपराध किया? कितनी आपूर्ति शृंखलाओं को तोड़ा गया? कार्रवाई का असली पैमाना छापे के दिन की सुर्खी नहीं, उसके बाद बाजार में आया बदलाव है।

वरन छापे पड़ते रहेंगे, माल पकड़ा जाता रहेगा, कार्रवाई होती रहेगी और खबरें छपती रहेंगी। जनता हर बार यही सोचेगी कि अब मिलावटखोरों का खेल खत्म! मगर कुछ दिन गुजरते ही दुकान फिर सज जाएगी, धंधा फिर चल पड़ेगा और मिलावट एक बार फिर बाजार में फरसटा भरने लगेगी। यह चक्र यूँ ही चलता रहेगा... जब तक कार्रवाई का डर मिलावटखोरों के मुनाफे पर भारी नहीं पड़ता...

अमेरिका के समक्ष अडिग रहे भारत

हाल में पहले अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो और फिर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रति जो नरमी दिखाई, वह इसी बात की पुष्टि करती है कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों में राष्ट्रीय हित सबसे अधिक महत्व रखते हैं। ट्रंप का यह कहना उल्लेखनीय तो है कि वे भारत से व्यापार समझौता करने के काफी करीब हैं और यह अलग किस्म का समझौता होगा, लेकिन आखिर उन पर कितना भरोसा किया जाए, क्योंकि वे पहले भी ऐसा कह चुके हैं। ट्रंप की नीतियां अनिश्चितता का परिचायक हैं।

वे कभी किसी देश और यहां तक सहयोगी देशों पर भी भारी टैरिफ या प्रतिबंध लगाने की धमकी देते हैं और फिर अपनी बात और फैसलों से पलट जाते हैं। उनके इस अस्थिर रवैये का सामना भारत भी करता आ रहा है, लेकिन भारत ने उनकी उलटी-सीधी बयानबाजी पर सदैव संयम और दृढ़ता दिखाने के साथ ही उनके दबाव में आने से इन्कार किया। ऐसा करके उसने अमेरिका और विश्व को यही संदेश दिया कि वह अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए किसी के दबाव में आने वाला नहीं है।

इसका बड़ा प्रमाण यह है कि भारत ने अमेरिका के इस दबाव के आगे झुकने से इन्कार किया कि वह रूस से तेल न खरीदे। इस मामले में भारत ने अमेरिकी धमकियों के जवाब में यही दोहराया कि वह अपने ऊर्जा हितों के लिए जो संभव है, वह करेगा। इसके बाद भी हमारे कुछ विपक्षी नेता और खासकर राहुल गांधी ने यह शोर मचाना नहीं छोड़ा कि मोदी सरकार ट्रंप के आगे नतमस्तक है अथवा उनके दबाव में है। पता नहीं अब वे क्या कहेंगे?

ट्रंप का यह कहना सकारात्मक अवश्य है कि वे भारत से व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने वाले हैं। उनके विदेश मंत्री का यह कहना भी महत्वपूर्ण है कि भारत रिफाइनिंग क्षेत्र की महाशक्ति है, पर इसका अर्थ अमेरिका का भारत के प्रति अचानक उदार हो जाना नहीं, बल्कि उसका ऊर्जा संकट से घिर जाना और उसके हल में भारत का मददगार दिखना है। चंद दिन पहले जो अमेरिका एक खास कानून बनाकर रूस से तेल खरीद के कारण भारत समेत पांच देशों पर सौ प्रतिशत टैरिफ लगाने वाला था, उसने यकायक अपने कदम पीछे खींच लिए। इसका कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गहराते ऊर्जा संकट में छिपा है।

ईरान के साथ अमेरिका के टकराव और यूक्रेन की ओर से रूस के तेल स्रोतों पर हमले से उत्पन्न ऊर्जा संकट ने अमेरिका सहित विश्व भर की चिंताएं बढ़ा दी हैं। कच्चे तेल और गैस की कीमतों में वृद्धि अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए भी बड़ी चुनौती बन गई है और वह भी ऐसे समय, जब वहां मध्यावधि चुनाव होने जा रहे हैं। ऊर्जा की बढ़ती कीमतें भी ट्रंप की लोकप्रियता में गिरावट का कारण बन रही हैं। ऊर्जा संकट का सामना कर रहे अमेरिका ने यह पाया कि भारत इस संकट से उसे और विश्व को भी राहत दिला सकता है। उसे यह अहसास इसलिए हुआ, क्योंकि भारत की रिफाइनरियां कच्चे तेल का बड़े पैमाने पर शोधन कर सकती हैं।

इसी कारण भारत यूरोप समेत कई देशों को शोधित तेल का निर्यात कर रहा है। भारत से शोधित तेल खरीदने वाले देशों में रूस भी शामिल है। अमेरिका चाहता है कि भारत उसके अधिपत्य वाले वेनेजुएला के तेल स्रोतों से अधिकाधिक कच्चा तेल खरीदकर उसे शोधित कर उसका निर्यात करे। वेनेजुएला का कच्चा तेल कच्चा ही अधिक गाढ़ा है। इसके शोधन की क्षमता बहुत कम देशों के पास है। भारत की कई रिफाइनरियां वेनेजुएला के गाढ़े कच्चे तेल का शोधन करने में सक्षम हैं। तथ्य यह भी है कि जहां अमेरिका में वर्षों से कोई नई रिफाइनरी नहीं लगी, वहीं यूरोपीय देशों ने अपनी कई रिफाइनरियां बंद कर दी हैं। ऐसे में अमेरिका समेत अन्य देशों की निगाह भारत की ओर है।

यदि भारत वेनेजुएला के ज्यादा से ज्यादा कच्चे तेल का शोधन करने लगता है तो शोधित तेल की वैश्विक आपूर्ति बढ़ सकती है। इसीलिए अमेरिकी विदेश मंत्री ने खास तौर पर जामनगर जाकर रिलायंस रिफाइनरी का दौरा किया। अब जब यह स्पष्ट है कि अमेरिका अपने ऊर्जा हितों की रक्षा के लिए भारत की



ओर देख रहा है, तब भारत को उससे व्यापार समझौता करते समय अपने हितों की रक्षा के लिए और दृढ़ता दिखानी होगी। भारत की सफलता अमेरिका से व्यापार समझौता होने से नहीं, बल्कि इससे तय होगी कि इस समझौते की शर्तें कितनी अनुकूल हैं।

भारत को अमेरिकी शर्तों का मूल्यांकन अपने हितों के आधार पर करते हुए उसके समक्ष यह स्पष्ट करना होगा कि यदि वेनेजुएला का तेल प्रतिस्पर्धी कीमतों पर उपलब्ध होगा, तभी वह उसका अधिक मात्रा में शोधन करेगा। यदि अमेरिका चाहता है कि भारत उसके ऊर्जा हितों की रक्षा में सहायक बने तो उसे भी भारतीय हितों की रक्षा के प्रति संवेदनशील होना होगा। इसकी अनदेखी न की जाए कि अमेरिका की मनचाही शर्तों के कारण ही महीनों की बातचीत के बाद भी व्यापार समझौता नहीं हो सका है। अमेरिका से व्यापार समझौते में भारतीय उद्योगों, किसानों, सेवा क्षेत्र और दीर्घकालिक आर्थिक हितों की पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य है।

अमेरिका के बदले रवैये को भारत को अपने लिए एक कूटनीतिक अवसर के रूप में देखना चाहिए। चूंकि ट्रंप स्वयं को एक कुशल सौदेबाज मानते हैं, इसलिए भारत को भी यह दर्शाना होगा कि उसका उद्देश्य उससे ऐसा व्यापार समझौता करना है, जो दोनों पक्षों के लिए समान रूप से लाभकारी हो। अंतरराष्ट्रीय समझौते इसी भावना के तहत होते हैं। भारत को इसलिए अडिग रहना होगा, क्योंकि अमेरिकी प्रशासन की नीतियां बदलती रहती हैं।

चूंकि दोनों देशों के बीच प्रौद्योगिकी, रक्षा, निवेश, व्यापार और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सहयोग के मजबूत आधार हैं, इसलिए भारत को एक ओर अमेरिका के साथ अपने रणनीतिक संबंधों को मजबूत बनाए रखना है तो दूसरी ओर अपनी स्वतंत्र विदेश नीति और आर्थिक हितों की रक्षा भी करनी है। ट्रंप का बदला रुख स्वागतयोग्य है, लेकिन उन पर न तो आंख मूंदकर भरोसा किया जा सकता है और न ही केवल उनके मन मुताबिक समझौता किया जा सकता है। अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में किसी नेता पर भरोसा महत्वपूर्ण तो है, परंतु इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है, उसके देश से दीर्घकालिक रिश्ते और राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा।



जामिया में छात्र आंदोलन तेज, यूनियन समेत 3 मांगों पर प्रदर्शन

नई दिल्ली। जामिया इस्लामिया में पिछले 14 दिन से छात्र भूख हड़ताल पर बैठे हैं. इन छात्रों की तीन मांगें हैं जिसमें मुख्य मांग जामिया मिल्लिया में स्टूडेंट यूनियन बहाली को लेकर है. भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों के साथ इस वक्त कैंपस के अंदर 100-150 छात्र धरने पर बैठे हुए हैं. छात्रों की मांग है कि छात्र संघ चुनाव की तारीख घोषित की जाए, मुख्य प्रॉक्टर को हटाया जाए और प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई वापस ली जाए. इन छात्रों में से एक छात्र फैजान ने बताया, "सिक्वोरिटी एडवाइजर यहां का गाली देकर बात करता है उसको तुरंत हटाने की मांग हमारी है. एडमिनिस्ट्रेशन परेशान करने का काम करता है." यूनिवर्सिटी प्रशासन ने छात्र संघ का संविधान तैयार करने के लिए कमेटी बनाई है, लेकिन छात्र चुनाव की समयसीमा घोषित करने की मांग पर अड़े हैं. 24 अक्टूबर को प्रदर्शन के दौरान छात्रों और सुरक्षा कर्मियों के बीच टकराव हुआ. इसके बाद यूनिवर्सिटी ने सभी कक्षाएं ऑनलाइन करने और लाइब्रेरी बंद रखने का फैसला लिया.

भूकंप के भयंकर झटकों से कांप उठा जापान

नई दिल्ली। जापान और वानुअतु आईलैंड में रविवार (25 अक्टूबर) की सुबह 2 अलग-अलग भूकंप आए. समाचार एजेंसी पीटीआई ने यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे (USGS) के हवाले से बताया कि को रविवार तड़के जापान के बोनिन द्वीप क्षेत्र में 6.5 तीव्रता का भूकंप आया. भूकंप की गहराई, संभावित नुकसान और क्या सुनामी की चेतावनी जारी की गई थी, इन सब चीजों को बारे में अभी तक कोई फिलहाल जानकारी नहीं मिली है. इसके अलावा जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियोसाइंसेज (GFZ) के अनुसार रविवार की सुबह वानुअतु द्वीप समूह में 6.16 तीव्रता का भूकंप आया. GFZ के मुताबिक रविवार को प्रशांत महासागर में स्थित वानुअतु द्वीप समूह में 6.2 तीव्रता का भूकंप आया. एजेंसी ने बताया कि यह भूकंप पृथ्वी की सतह से 125 किलोमीटर (78 मील) की गहराई पर आया था. दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित द्वीप राष्ट्र वानुअतु पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के भूकंपीय रूप से एक्टिव सक्रिय क्षेत्र में आता है. यहां टेक्टोनिक प्लेटों की हलचल के कारण अक्सर भूकंप आते रहते हैं . प्रशांत महासागर में स्थित वानुअतु में 6.2 तीव्रता का भूकंप आया.

भारत-जर्मनी के बीच डील!

नई दिल्ली। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि जर्मनी के पास प्रयोगशालाओं में होने वाले अनुसंधान को कारखानों तक पहुंचाने और उसे उपयोगी समाधान में बदलने की खास क्षमता है. भारत जर्मनी के इस अनुभव से सीखना चाहता है और अपनी बड़ी आबादी, युवा प्रतिभा तथा उत्पादन क्षमता के दम पर इस सहयोग को बड़े स्तर तक ले जा सकता है. उन्होंने कहा कि भारत और जर्मनी के बीच मजबूत साझेदारी, संस्थानों और कारोबारियों के आपसी सहयोग तथा भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) से अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में नए अवसर खुले हैं. गोयल ने कहा कि भारत और जर्मनी मिलकर नई तकनीक विकसित करने, डिजाइन तैयार करने, नवाचार करने और भारत में उत्पादन करने की दिशा में काम कर सकते हैं. इससे भारतीय बाजार की जरूरतें पूरी करने के साथ दुनिया के अन्य बाजारों तक भी पहुंच बनाई जा सकेगी।

'मोदी का बाप भी जाएगा', पीएम पर खरगे के विवादित बयान से हंगामा



पटना। पटना में पीएम मोदी को लेकर कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे विवादित बयान दिया है. उन्होंने बापू सभागार में कहा कि बंगाल बिहार महाराष्ट्र हरियाणा की सरकार चोरी की सरकार है. यह वोट चोरी वाली सरकार है. इस पर हंगामे की स्थिति बन गई. इस दौरान एक व्यक्ति ने कहा मोदी कभी नहीं जाएगा. इस पर मंच से खरगे ने गरजते हुए अंदाज में जवाब दिया कि मोदी का बाप भी जाएगा. उन्होंने आगे कहा कि महंगाई चरम पर है. प्याज महंगे हो रहे हैं. गरीब आदमी दाल रोटी खाता है. दाल नहीं तो प्याज रोटी खाता है. आज प्याज महंगा हो गया, यह मोदी लोगों का गला काट रहा है. पार्लियामेंट चलता है, तो मोदी और शाह डर के पार्लियामेंट के अंदर नहीं आते हैं. राहुल गांधी बाहर गए हैं. अपने काम से गए हैं. जब वापस आएंगे तो इन लोगों की अच्छे से मरम्मत होगी. सिर्फ राहुल राहुल यह लोग करते हैं. इन लोगों के सपने में भी राहुल गांधी आते हैं.

खड़गे ने कहा देश में जितने ज्योतिर्लिंग हैं, उसमें से एक लिंग में हूं. श्री कृष्ण सिंह जी को उनके 139वीं जयंती पर नमन करता हूं. बाबू लोकतंत्र को मजबूत करने वाले व्यक्ति थे. कमजोर वर्गों को उन्होंने हमेशा आगे किया. जमींदारी प्रथा को श्री कृष्ण सिंह ने खत्म

किया. लैंड रिफॉर्म के लिए बड़ा काम श्री कृष्ण सिंह ने किया है. श्री बाबू भूमिहार जाति से थे, उनके जाति के लोग ही जमींदार थे. उसके बावजूद भी उन्होंने जमींदारी प्रथा को हटाया. कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, 'मूलभूत सुविधाओं और बिहार के शिक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था पर खूब काम किया. फैक्ट्री और इंडस्ट्री श्री बाबू के कार्यकाल में ही बिहार में लगे. जब आरएसएस और दूसरी शक्तियां दंगा फैलाने में लगी थी, तो बाबू ने उसका मजबूती से सामना किया. बाबू ने छुआछूत के खिलाफ मुहिम चलाया. बाबा बैधनाथ धाम में दलितों के एंट्री पर पाबंदी थी, उनको एंट्री बाबू ने दिलाया. खड़गे ने कहा कि छुआछूत के मानसिकता वाले लोग आज भी आरएसएस और बीजेपी में भरे हुए हैं. जब तक देश में रss खत्म नहीं होती शांति नहीं आ सकती है.

नीतीश कुमार पर बोले- जब आइडियोलॉजी...

इसके अलावा उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर कहा कि जो समाजवादी सोच के थे, वो बीजेपी आरएसएस के गोद में बैठ गए. जब आपका आइडियोलॉजी कमजोर होती है, तब ऐसी चीज होती हैं. हमने तो कुर्बानियां दीं. गांधी जी को मार दिया गया. इंदिरा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई. राजीव गांधी को मार दिया गया. हम मरने वाले लोग हैं. आज राहुल गांधी लड़ रहा है.

हल्द्वानी की घटना पर क्या बोले खरगे?

उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के हल्द्वानी में 8 अगस्त 2026 हवन कार्यक्रम के बाद मंच को शुद्धिकरण किया गया. आजादी के कितने वर्ष बाद अगर छुआ छूत है तो देश कहां खड़ा है. हमें छुआछूत और शुद्धिकरण करने वाले को देश से भागना है. मौजूदा सरकार आज के डेट में अछूतों को ईंसान नहीं समझती. 8 अगस्त 2026 को शुद्धिकरण वाले मामले के बाद आज तक पीएम मोदी की जुबान नहीं खुली. हम बिहार वासियों से अनुरोध करने आए हैं कि अछूत वाली मानसिकता को जड़ से खत्म करो. जिस तरह बाबू ने बैधनाथ धाम मंदिर में लोगों को लेकर घुसे वेसे हम सब लोग को घोषणा है. बाबू- महात्मा गांधी की पहली मुलाकात बनारस में हुई. बाबू ने 8 साल आजादी की लड़ाई के लिए जेल में काटे.. क्या बीजेपी आरएसएस वाले ने जेल काटा है, आजादी की लड़ाई में?

इंडिया ब्लॉक की रैली आतंक और अराजगता फैलाने का बहाना: गिरिराज सिंह

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने 1 नवंबर को प्रस्तावित इंडिया ब्लॉक की रैली को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और विपक्षी गठबंधन पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन को वापस पाने के लिए जनता के बीच विश्वसनीयता कायम नहीं कर पा रहे हैं. इसलिए अब SIA का बहाना बनाकर देश में अराजकता और आतंक का माहौल बनाना चाहते हैं. गिरिराज सिंह ने कहा कि एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी लगातार चुनाव जीत रहे हैं. वहीं, राहुल गांधी जिन राज्यों में चार-चार दशक पहले हारे थे, वहां आज भी कांग्रेस का खाता तक नहीं खुल पा रहा है. राहुल गांधी के विरोध प्रदर्शनों का व्यापारी वर्ग और आम जनता दोनों विरोध कर

रहे हैं, इसके बावजूद वे अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं.

अर्बन नक्सल जैसी गतिविधियां

उन्होंने कहा कि इस तरह की राजनीति से कांग्रेस अगले तीन दशक तक सत्ता में नहीं आ पाएगी. सत्ता में वापसी का रास्ता जनता के बीच जाकर, उनकी समस्याएं सुनने से निकलता है, अर्बन नक्सल जैसी गतिविधियों से नहीं. गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी अपनी खोई हुई जमीन वापस नहीं ले पा रहे हैं और जहां वे हार चुके हैं, वहां नई जमीन मिलने की



कोई उम्मीद भी नहीं दिख रही है उन्होंने तंज करसते हुए कहा कि "जहां कांग्रेस जीत जाती है वहां चुप्पी साध ली जाती है और जहां हार जाती है, वहां SIA जैसे मुद्दे उठाए जाते हैं. जब उनसे पूछा गया कि 1 नवंबर को होने वाली रैली की तारीख को लेकर विवाद हो रहा है क्योंकि उसी दिन 1984 के सिख दंगों की बरसी भी है, तो इस पर गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी को सिख दंगों की कोई चिंता नहीं है. ऐसी तारीख का चयन करना सिख समुदाय के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है और यह तारीख उनके लिए ही काल साबित होगी."

हम असहाय होकर केवल तमाशा नहीं देख सकते: विदेश मंत्री

नई दिल्ली। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने युद्ध को लेकर अपनी राय रखी है. उन्होंने कहा है कि कहीं भी होने वाला युद्ध हर जगह शांति के लिए खतरा है. उन्होंने यूक्रेन और मीडिल ईस्ट में जारी संघर्ष को लेकर भी चिंता जाहिर की और इससे पड़ने वाले दुनिया पर व्यापक असर को लेकर अपनी बात रखी है. संयुक्त राष्ट्र दिवस के मौके पर दिल्ली में आयोजित चिन्मय अमृत महोत्सव ग्लोबल सम्मेलन में बोलते हुए जयशंकर ने भारत का यह रुख दोहराया कि संघर्ष को सुलझाने का एकमात्र तरीका बातचीत और कूटनीति है. इस दौरान उन्होंने यूक्रेन पर रूस के हमले और पश्चिम एशिया में अमेरिका, इजरायल और ईरान से जुड़ी गंग का जिक्र किया. विदेश मंत्री ने कहा कि आज दुनिया में दो बड़े संघर्ष चल रहे हैं. यूक्रेन में और पश्चिम एशिया या मध्यपूर्व में, ऐसे समाज, अर्थव्यवस्थाएं और लोग, जिनका इन मामलों से कोई लेना देना नहीं है, असल में उन्हें ही इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है.

उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी सिर्फ मूकदर्शक बनकर नहीं रह सकता. भारत इन संघर्षों को सुलझाने के लिए अपने स्तर पर कोशिश कर रहा है. शांति बहाल



करने के लिए अन्य देशों के साथ मिलकर काम करने को तैयार है. एस जयशंकर ने आगे कहा कि हम असहाय होकर केवल तमाशा नहीं देख सकते. जब हम यह कहते हैं कि बातचीत और कूटनीति ही एकमात्र समाधान है, तो भारत दुनिया की भावनाओं को ही व्यक्त कर रहा है. हम खुद भी कोशिश कर रहे हैं. इस दिशा में अन्य साझेदारों के साथ मिल करने काम करने के लिए तैयार हैं.

'आतंकवाद का इस तरह इस्तेमाल अस्वीकार्य'

विदेश मंत्री ने कहा कि आतंकवाद का इस्तेमाल राज्य की नीति के एक साधन के रूप में करना, बिल्कुल अस्वीकार्य है. इसे न तो सही ठहराया जा सकता है, न ही इसके लिए कोई तर्क दिया जा सकता है. आतंकवाद शांति के लिए एक और घातक खतरा है. उन्होंने कहा कि आतंकवाद इसलिए खतरा बना हुआ है, क्योंकि सभी देश इस पर जीरो टॉलरेंस नहीं अपनाते हैं. इतिहास में इतने सबक मिलने के बावजूद कुछ लोग अभी भी राजनीतिक नफे नुकसान को ज्यादा अहमियत देते हैं।

भारत ने सऊदी में नागरिकों के लिए जारी की एडवाइजरी

नई दिल्ली। सऊदी अरब में स्थित भारत के दूतावास ने रविवार को सऊदी अरब में रह रहे भारतीय नागरिकों को स्थानीय नियमों का पालन करने के लिए निर्देश जारी किए हैं. सऊदी अरब के डिरेक्टरेट ऑफ सिवल डिफेंस ने नोट जारी कर सऊदी में फंसे सभी विदेशी नागरिकों से मिसाइलों और ड्रोन को हवा में रोकने से जुड़ी घटनाओं का वीडियो बनाने या उनसे संबंधित जानकारी प्रसारित करने से बचने की सलाह दी. यह परामर्श क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच आया है. यमन के हूती विद्रोहियों की ओर से नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाकर किए जा रहे ड्रोन और मिसाइल हमलों की कई घटनाओं के कारण क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है.

भारतीय दूतावास ने सऊदी अरब के नागरिक सुरक्षा निदेशालय की ओर से जारी अधिसूचना को सोशल मीडिया पर साझा करते हुए कहा, "सऊदी अरब में रह रहे भारतीय समुदाय से स्थानीय नियमों और विनियमों का पालन करने का अनुरोध किया जाता है." अधिसूचना में कहा गया है, "मिसाइलों और ड्रोन को रोकने की कार्रवाई तथा उनके गिरने या प्रभाव वाले स्थानों से जुड़ी जानकारी की वीडियो बनाना, उसे प्रसारित या साझा करना आपको कानूनी कार्रवाई के दायरे में ला सकता है."



अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में जापान ने मंगल ग्रह के रहस्यमयी चांद फोबोस से मिट्टी और चट्टानों के नमूने लाने के लिए अपना महत्वाकांक्षी MMX (Martian Moons eXploration) मिशन सफलतापूर्वक रवाना कर दिया है. यह ऐतिहासिक अंतरिक्ष यान तानेगाशिमा स्पेस सेंटर से शक्तिशाली H3 रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष की ओर रवाना हुआ. इस वैश्विक घटनाक्रम के बीच अब यह सवाल तेजी से उठ रहा है कि दुनिया भर की अंतरिक्ष एजेंसियां चांद से अब तक कितनी मिट्टी धरती पर ला चुकी हैं और क्या इस मिट्टी का इस्तेमाल इमारत बनाने के लिए किया जा सकता है? चलिए समझें.

जापान का नया अंतरिक्ष मिशन

जापानी अंतरिक्ष एजेंसी (JAXA) का MMX मिशन मंगल के उपग्रह फोबोस से सतह के नमूने एकत्र करने की दिशा में एक बेहद ऐतिहासिक कदम है. इस तरह के अभियानों का मुख्य उद्देश्य सौरमंडल की उत्पत्ति और ग्रहों की संरचना को बेहतर ढंग से समझना होता है. हालांकि, ग्रहों और उपग्रहों से मिट्टी के नमूने लाने का इतिहास नया नहीं है. इससे पहले भी अमेरिका, रूस और चीन जैसी महाशक्तियां चंद्रमा की सतह से मिट्टी और चट्टानों के विभिन्न नमूने धरती पर लाने में सफलता हासिल कर चुकी हैं. चंद्रमा की सतह से सबसे अधिक मात्रा में नमूने लाने का रिकॉर्ड अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा के नाम दर्ज है. साल 1969 से 1972 के बीच चले नासा के ऐतिहासिक अपोलो अभियान (अपोलो 11 से लेकर अपोलो 17 तक) के दौरान अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की सतह से लगभग 382 किलोग्राम वजनी चट्टानें और धूल धरती पर लेकर आए थे. यह अब तक

सा कमरा या सामान्य दीवार खड़ी करने के लिए भी कंटन ईट, बजरी और सीमेंट की जरूरत पड़ती है. अंतरिक्ष यात्रियों और रोबोटिक मिशनों द्वारा लाई गई करीब 384 से 400 किलोग्राम मिट्टी की यह सीमित मात्रा इतनी कम है कि इससे केवल कुछ प्रायोगिक ईंटें या लैब परीक्षण के छोटे प्रोटोटाइप ही तैयार किए जा सकते हैं. भले ही धरती पर लाई गई मिट्टी से इमारत न बने, लेकिन वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया है कि चांद की मिट्टी में निर्माण सामग्री बनने की पूरी क्षमता है. भविष्य में जब चांद पर मानव बस्तियां बसाई जाएंगी, तो धरती से भारी निर्माण सामग्री ले जाना बहुत खर्चीला होगा।



25 साल पुराना रिश्ता खत्म! जेम्स एंडरसन ने लैंकशायर को कहा अलविदा;

लंदन। इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने जुलाई 2024 में यानी करीब 2 साल पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया था, लेकिन घरेलू क्रिकेट खेलना जारी रखा था. लेकिन अब उन्होंने घरेलू टीम लैंकशायर को भी अलविदा कह दिया है. लैंकशायर ने एंडरसन का 2027 सीजन के लिए कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया, जिसके बाद इंग्लिश खिलाड़ी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया और बताया कि उनका टीम के साथ 25 साल पुराना रिश्ता खत्म हो गया. एंडरसन ने लिखा, "मैंने बचपन से लंकाशायर को सपोर्ट किया और उनके लिए 25 साल तक खेलना मेरे लिए एक सपने के सच होने जैसा था. ओल्ड ट्रैफर्ड में खेलने के लिए मैदान पर उतरना मेरे लिए हमेशा से बहुत खास रहा है, और वहां खेलने की मेरी कुछ बेहतरीन यादें हैं, जिनमें कप्तान बनने का सम्मान भी शामिल है. अगर यह मेरे हाथ में होता, तो इसका अंत इस तरह न होता, लेकिन मैं खिलाड़ियों और फैस को भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं."यहां गौर करने वाली बात यह है कि एंडरसन ने अंत होने की बात कही. लेकिन उन्होंने संन्यास का जिक्र नहीं किया. घरेलू क्रिकेट में 44 साल के एंडरसन आगे और खेलेंगे या नहीं, इस पर कुछ साफ नहीं हो सका है.

18 की उम्र में बांग्लादेशी खिलाड़ी का निधन

नई दिल्ली। बांग्लादेश से क्रिकेट जगत के लिए बड़ी दुख भरी खबर आई है. युवा क्रिकेटर मेहदी हसन हदोय का गंभीर बीमारी के चलते निधन हो गया. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया के जरिए शेयर की. कुछ दिन पहले अफगानिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शापूर जादरान बीमारी से लड़ते हुए जिंदगी की जंग हार गए थे. अब एक बार फिर क्रिकेट जगत में मातम पसर गया. शनिवार (24 अक्टूबर) को बांग्लादेश बोर्ड ने रिलीज में बताया कि हदोय चट्टोग्राम डिबीजन की अंडर-18 टीम का प्रतिनिधित्व कर चुके थे. वह एक तेज गेंदबाज थे. कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में उनकी उम्र 18 साल बताई गई है. वह ल्यूकेमिया बीमारी से जूझ रहे थे. सोशल मीडिया पर जारी की गई रिलीज में लिखा गया, "बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने युवा क्रिकेटर मेहदी हसन हदोय के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है. ल्यूकेमिया से जूझने के बाद आज ढाका में उनका निधन हो गया."

सूर्यकुमार यादव ने दिखाई अपनी बेसबॉल स्किल्स

नई दिल्ली। मेजर लीग बेसबॉल (MLB) ने अपने पहले 'MLBx मुंबई 3-ऑन-3' बेसबॉल इवेंट का आयोजन मुंबई के अंधेरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्थित मुंबई फुटबॉल एरिना में किया. इसमें सूर्यकुमार यादव, जितेश शर्मा आदि भारतीय क्रिकेटरों और बेसबॉल खिलाड़ियों ने एक साथ हिस्सा लिया. टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सूर्या ने भी बेसबॉल में अपना हाथ आजमाया. सूर्यकुमार यादव मेजर लीग बेसबॉल इंडिया के एंबेसडर हैं. उनके साथ जितेश शर्मा, शार्दुल ठाकुर, दीपक चाहर, काशवी गौतम और राधा यादव जैसे भारतीय क्रिकेटरों ने, पूर्व MLB स्टार्स निक स्विसर, जेक एरियेटा और एड्रियन गोंजालेज के साथ मिलकर दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया.हिस्सा लेने वाले सभी खिलाड़ियों को 4 टीमों में बांटा गया था. मेजर लीग बेसबॉल की कुछ सबसे ऐतिहासिक फ्रेंचाइजी जैसे 'रेड सॉक्स', 'कब्स', 'डॉजर्स', 'यांकीज' के नाम पर इन टीमों के नाम रखे गए थे।

कौन बने मुंबई इंडियंस का अगला कप्तान?

कार्तिक ने रोहित शर्मा का किया समर्थन



नई दिल्ली। मुंबई इंडियंस ने हाल ही में कीरोन पोलार्ड को अपना नया हेड कोच नियुक्त किया है, जिसके बाद नए कप्तान को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं. हालांकि हार्दिक पांड्या टीम से अभी अलग नहीं हुए हैं, लेकिन माना जा रहा है कि IPL 2027 के लिए वह ट्रेड होकर किसी दूसरी फ्रेंचाइजी में जा सकते हैं. बड़ी उम्मीदों के साथ एमआई ने उन्हें कप्तान बनाया था, जिसके लिए उन्होंने रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाया था. क्या फिर

रोहित ही कप्तानी संभाल सकते हैं? दिनेश कार्तिक ने इसका समर्थन किया.रोहित शर्मा की कप्तानी में मुंबई इंडियंस ने 5 आईपीएल खिताब जीते, जिन्हे हटाकर फ्रेंचाइजी ने 2024 सीजन के लिए हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया था. उन्होंने गुजरात टाइटंस को बतौर कप्तान पहले ही सीजन में चैंपियन बनाया था, दूसरे साल टीम फाइनल तक पहुंची. हालांकि पांड्या की कप्तानी का जादू एमआई में नहीं चला. 3 में से 2 सीजन (2024, 2026) टीम प्लेऑफ तक भी क्वालीफाई नहीं कर पाई.

क्या बोले दिनेश कार्तिक

दिनेश कार्तिक ने क्रिकबज से बात करते हुए कहा, "मुझे लगता है कि वे नए कप्तान की तलाश में हैं. कुछ समय बाद घोषणा भी कर दें. रोहित शर्मा क्यों नहीं? सफल कप्तानों में एक हैं और अगर वही कप्तान बनते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं. अगर वह उपलब्ध हैं तो उनकी सेवा क्यों न ली जाए. उनमें काबिलियत है, वह अच्छे कप्तान हैं जिनकी ओर खिलाड़ी आकर्षित होते हैं." कार्तिक को लगता है कि रोहित सबसे अच्छे विकल्प हैं.मुंबई इंडियंस के नए कप्तान बनने की दौड़ में तिलक वर्मा भी शामिल हैं, जिन्हें रेस में सबसे आगे माना जा रहा है. हार्दिक पांड्या के कप्तान बनने के बाद न सिर्फ प्रदर्शन बल्कि ड्रेसिंग रूम के माहौल को लेकर भी चर्चाएं रही. अब कीरोन पोलार्ड नए हेड कोच बनाए गए हैं, जिनकी हार्दिक पांड्या के साथ अच्छी बॉन्डिंग रही है. क्या अब पांड्या के एमआई में बने रहने की भी संभावना है. जब तक आधिकारिक घोषणा नहीं हो जाती, कुछ नहीं कहा जा सकता.

राहुल-जायसवाल फ्लॉप, न्यूजीलैंड के खिलाफ मुश्किल में टीम इंडिया

नई दिल्ली। न्यूजीलैंड ए के खिलाफ टीम इंडिया बहुत बुरे हाल में है. न्यूजीलैंड की पहली पारी 317 रन पर सिमट गई थी, जिससे उसे पहली पारी में 204 रनों की विशालकाय बढ़त मिली. अब हाल ऐसे हैं कि इंडिया ए पर पारी की हार का खतरा मंडराने लगा है. दूसरे दिन स्टम्पस तक भारतीय टीम का स्कोर 106/2 है. वह अब भी 98 रनों से पीछे है.भारतीय टीम को पारी की हार टालने के लिए कम से कम 98 रन और बनाने हैं. वहीं जीत के लिए दावेदारी पेश करनी है तो दूसरी पारी में बहुत बड़ा स्कोर खड़ा करना होगा. बताते चलें कि टीम इंडिया की पहली पारी मात्र 113 रनों पर सिमट गई थी.



फिलहाल दूसरी पारी में देवदत्त पडिक्कल और साई सुदर्शन क्रीज पर टिके हैं और उनके बीच 96 रनों की साझेदारी हो चुकी है.

यशस्वी जायसवाल पहली पारी में महज 17 रन बनाकर आउट हो गए थे. वहीं राहुल तो खाता तक नहीं खोल पाए थे. दूसरी पारी में भी राहुल और जायसवाल का बल्ला खामोश रहा, जहां उन्होंने क्रमशः 4 और 5 रन बनाए. राहुल के स्कोर तक ही पहुंची थी कि दोनों सलामी बल्लेबाज केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल, दोनों आउट हो चुके थे।

ITR फाइलिंग की बढ़ी तारीख, अब चूके तो 5000 रुपये जुर्माना

नई दिल्ली।केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने उन करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय-सीमा 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 21 नवंबर, 2026 कर दी है. यह उनके लिए है, जिनके खातों का टैक्स ऑडिट कराना अनिवार्य है. यह तारीख इन टैक्सपेयर्स के लिए बेहद अहम है क्योंकि अगर इन्होंने इस तारीख के बाद रिटर्न फाइल किया तो फिर भारी लेट फीस के साथ पेनाल्टी का सामना करना पड़ेगा.पहले इन टैक्सपेयर्स के लिए ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर 2026 थी, जिसे CBDT ने त्योहारी सीजन और काम के भारी दबाव को ध्यान में रखते हुए 21 दिन आगे बढ़ाकर 21 नवंबर 2026 कर दिया था. ऐसे करदाता जिनकी आय व्यापार या पेशेवर सेवाओं से होती है और जिन्हें ऑडिट रिपोर्ट जमा करना अनिवार्य है, उन्हें जुर्माने और टैक्स नोटिस से बचने के लिए 21 नवंबर तक अपना रिटर्न दाखिल करना होगा. इनमें घरेलू और विदेशी कंपनियां, ऐसे बड़े कारोबारी जिनका सालाना टर्नओवर 1 करोड़ रुपये से ज्यादा है, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA), वकील, आर्किटेक्ट और इंजीनियर्स जैसे पेशेवर, जिनकी सालाना ग्रांस् रिसीट्स 50 लाख रुपये से अधिक या चुनिंदा मामलों में 75 लाख रुपये है. नौकरीपेशा लोगों और आम व्यक्तिगत करदाताओं, जिन्हें ऑडिट की जरूरत नहीं होती।

ट्रंप का यू-टर्न, कई सामानों पर खत्म किया 50% टैरिफ

वाशिंगटन। अमेरिका और कनाडा के बीच व्यापार को लेकर चल रहा तनाव एक बार फिर चर्चा में है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा से आने वाले कुछ उत्पादों पर लगाए गए भारी आयात शुल्क में राहत देने का फैसला किया है. यह कदम ऐसे समय उठाया गया है, जब अमेरिका में मध्यावधि चुनाव नजदीक हैं और महंगाई आम लोगों के लिए बड़ा मुद्दा बनी हुई है. हालांकि, इस फैसले का मतलब कनाडा के सभी सामानों से टैरिफ हटाना नहीं है, क्योंकि कुछ दूसरे उत्पादों पर शुल्क लगाने का दायरा बढ़ाया गया है.

कुछ उत्पादों पर बढ़ेगा टैरिफ का दायरा

जहां कुछ कनाडाई सामानों को राहत दी गई है, वहीं दूसरी ओर कई उत्पादों को फिर से 50 प्रतिशत टैरिफ के दायरे में शामिल किया गया है. इनमें कालीन, पेंट, शैंपू, एयर कंडीशनिंग उपकरण और कुछ अन्य सामान शामिल हैं.इससे साफ है कि अमेरिका की



कागज से जुड़े उत्पाद, कुछ मशीनें, रेफ्रिजरेशन उपकरण और पैकेजिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले कुछ सामान शामिल हैं.रिपोर्ट के मुताबिक, इन बदलावों को 30 अक्टूबर 2026 से लागू किया जाना है. सरकार का कहना है कि यह कदम अमेरिकी कारोबार पर पड़ने वाले असर को कम करने और व्यापार से जुड़े हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से उठाया गया है.



शाहीन अफरीदी ने सबसे तेज 150 विकेट लेने में तोड़ा रिकॉर्ड

नई दिल्ली। शाहीन अफरीदी इन दिनों इंग्लैंड और श्रीलंका के साथ खेली जा रही वनडे ट्राई सीरीज में पाकिस्तान की कप्तानी कर रहे हैं. उनकी कप्तानी में पाकिस्तान सीरीज के तीसरे मैच में इंग्लैंड के सामने हैं. शाहीन ने मुकाबले की पहली पारी में धारदार गेंदबाजी करते हुए सबसे तेज 150 वनडे विकेट पूरे करने वाले पाकिस्तानी गेंदबाजों की लिस्ट में खुद को शुमार कर लिया. खास आंकड़े को छूते हुए शाहीन ने पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज शोएब अख्तर और वकार यूनुस को पछाड़ दिया. अब वह पाकिस्तान के लिए वनडे में सबसे तेज 150 विकेट पूरे करने वाले दूसरे गेंदबाज बन गए हैं. इस लिस्ट में पूर्व स्पिनर सकलैन मुश्ताक पहले पायदान पर हैं. शाहीन ने 80 मैचों में 150 वनडे विकेट का आंकड़ा छुआ, जबकि टॉप पर मौजूद सकलैन मुश्ताक ने 78 मैचों में ही यह कमाल कर दिया था. वहीं वकार यूनुस और शोएब अख्तर 91-91 मैचों के साथ शाहीन अफरीदी के नीचे पहुंच गए हैं. लिस्ट में उनके नीचे उमर गुल मौजूद हैं.

वनडे में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले पाकिस्तानी गेंदबाज

सकलैन मुश्ताक- 78 मैच
शाहीन शाह अफरीदी- 80 मैच*
वकार यूनिस- 91 मैच
शोएब अख्तर- 91 मैच
सईद अजमल- 93 मैच

तीसरे टी20 में ईशान की वापसी, वैभव होंगे बाहर

नई दिल्ली। भारत और न्यूजीलैंड का तीसरा टी20 मैच 27 अक्टूबर को वेलिंगटन में खेला जाएगा. पहले दोनों मैच जीतकर टीम इंडिया सीरीज में 2-0 की बढ़त बना चुकी है. दूसरे मुकाबले को याद करें तो



ईशान किशन को ग्रेडिन इंजरी की वजह से प्लेइंग इलेवन में शामिल नहीं थे. खबर है कि मैनेजमेंट एहतियात के तौर पर ईशान को तीसरे टी20 से भी बाहर बैठा सकता है. ऐसे में वैभव सूर्यवंशी पर एक बार फिर सबकी नजरे टिकी होंगी, जो दूसरे मुकाबले में नंबर-3

पर खेले थे.दूसरे मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी नंबर-3 पर खेले थे, लेकिन वह सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हो गए थे. वैभव नंबर-3 पर भारी दबाव में दिखे थे, क्योंकि वह पहली बार इस क्रम पर बैटिंग कर रहे थे. अगर ईशान तीसरे टी20 से भी बाहर रहते हैं और वैभव अंतिम-11 में बने रहते हैं तो संभव है कि संजय सैमसन तीसरे क्रम पर आ सकते हैं, क्योंकि उन्हें नंबर-3 पर खेलने का अनुभव है. ईशान की जगह विकेटकीपर बल्लेबाज कुमार कुशाग्र भी बल्लेबाजी का एक विकल्प मौजूद हैं.

भारत से लेकर फ्रांस तक किस पर कितना बोझ

कर्ज के दलदल में दुनिया!



दुनिया के कई देश इस समय बढ़ते सरकारी कर्ज और उस पर लगने वाले ब्याज के बोझ से जूझ रहे हैं. अमेरिका, चीन और जापान जैसे बड़े देशों पर खरबों डॉलर का कर्ज है, वहीं फ्रांस में भी उधारी महंगी होने से आर्थिक दबाव बढ़ रहा है. जब सरकारों को कर्ज चुकाने के लिए ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है, तो इसका असर आम लोगों से जुड़ी योजनाओं और जरूरी सेवाओं पर भी पड़ सकता है. दरअसल, सरकारें सड़क, रेलवे, अस्पताल, शिक्षा और रक्षा जैसे कामों के लिए कई बार उधार लेती हैं. इसके लिए सरकारी बॉन्ड जारी किए जाते हैं, जिन्हें बैंक, बीमा कंपनियां और दूसरे निवेशक खरीदते हैं. लेकिन जब ब्याज दरें बढ़ती हैं, तो सरकारों के लिए कर्ज चुकाना और नया कर्ज लेना महंगा हो जाता है.

सरकारें आखिर कर्ज क्यों लेती हैं?

सरकारों को टैक्स और दूसरे स्रोतों से कमाई होती है, लेकिन कई बार खर्च आमदनी से ज्यादा हो जाता है. इस अंतर को पूरा करने के लिए सरकारें सरकारी बॉन्ड जारी करके निवेशकों से पैसा जुटाती हैं. हालांकि, कई बार सरकारों पुराने कर्ज की अदायगी के लिए भी नया कर्ज लेती हैं.उदाहरण के तौर पर, अगर सरकार 100 रुपए का बॉन्ड जारी करती है और कोई निवेशक

इसे खरीदता है, तो वह सरकार को 100 रुपए उधार देता है. वहीं अगर बॉन्ड पर सालाना ब्याज दर 2.5% है, तो सरकार को हर साल 2.50 रुपए ब्याज देना होगा. 10 साल के बॉन्ड पर इस दर से कुल 25 रुपये ब्याज देने के बाद सरकार तय शर्तों के अनुसार निवेशकों से पैसा की मूल रकम भी लौटाती है.

दुनिया के किस देश पर कितना सरकारी कर्ज है?

आंकड़ों के मुताबिक, सरकारी कर्ज के मामले में अमेरिका सबसे आगे है.

मजदूरों के PAN-आधार से खोले 37 खाते, बैंक मैनेजर्स ने की 7.3 करोड़ की ठगी

नई दिल्ली। अगर आपने बैंक खुलवाया होगा या फिर लोन लिया है तो आप इस बारे में जानते होंगे कि इसके लिए कुछ जरूरी दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड. ऐसे में सोचिए, अगर आपने लोन लेने के लिए किसी को अपने दस्तावेज दिए, लेकिन इसी का इस्तेमाल साइबर ठगी में होने लगे तो जाहिर सी बात है कि ये परेशानी का कारण बन सकता है.ऐसा ही एक मामला दिल्ली से सामने आया है, यहां पर दिहाड़ी मजदूरों को लोन दिलाने की बात कहकर उनके दस्तावेजों को लेने और बैंक अकाउंट खोलने का मामला सामने आया है. हैरानी की बात तो ये है कि इन अकाउंट से जुड़े साइबर अपराध के मामलों में लगभग 7.3 करोड़ रुपये के लैन-देन की जांच पुलिस कर रही है. बता दें कि जब पुलिस ने जांच की तो जांच के दौरान ही पुलिस को बड़ी संख्या में कई दस्तावेज मिले. इनमें शामिल है- पैन कार्ड - 60, आधार कार्ड- 63, 11 सिम कार्ड 7 डेबिट कार्ड, 7 चेक बुक, पासपोर्ट साइज फोटो- 55। बता दें कि पुलिस ने एक निजी बैंक त्रि नगर शाखा से जुड़े अकाउंट की जांच की थी. पुलिस की जांच में मयंक कूपर का नाम सामने आया है. आरोप ये है कि व्यक्ति दिहाड़ी मजदूरों को लोन दिलाने का झांसा देता था।

स्मृति ईरानी ने दिया कार्यकर्ताओं को अनुशासन का संदेश

रायपुर पहुंचीं भाजपा प्रदेश प्रभारी, कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में हुआ जोरदार स्वागत

शहरसत्ता/रायपुर। छत्तीसगढ़ में भाजपा की प्रदेश प्रभारी बनने के बाद स्मृति ईरानी अपने पहले दौर पर रायपुर पहुंचीं। यहां आते ही उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को अनुशासन का संदेश दिया। भाजपा कार्यालय परिसर में उन्होंने स्पष्ट किया कि बैठक में जिन लोगों को बुलाया गया है, केवल वही कार्यालय में मौजूद रहें। बिना किसी काम या बुलावे के कार्यकर्ताओं को कार्यालय नहीं आना चाहिए। स्मृति ईरानी के इस निर्देश को प्रदेश में संगठनात्मक व्यवस्था को मजबूत करने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है। अपने दो दिवसीय प्रवास के दौरान वह पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, पदाधिकारियों, पूर्व सांसदों, पूर्व विधायकों और जिला स्तर के नेताओं के साथ बैठकें कर संगठन की स्थिति और आगामी रणनीति पर चर्चा करेंगी। छत्तीसगढ़ बीजेपी की प्रदेश प्रभारी बनाए जाने के बाद पहली बार स्मृति ईरानी रायपुर पहुंचीं हैं। छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रभारी का रायपुर एयरपोर्ट पर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। एयरपोर्ट से स्मृति ईरानी सीधे भाजपा प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर पहुंचीं, जहां भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव सहित पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने भी स्मृति ईरानी का स्वागत किया, इस दौरान स्मृति ईरानी ने पार्टी नेताओं और पदाधिकारियों से मुलाकात कर सियासी हालात की जानकारी ली। स्मृति ईरानी के पहले छत्तीसगढ़ प्रवास को लेकर संगठन में काफी उत्साह है। 2 दिवसीय दौरे के दौरान स्मृति ईरानी प्रदेश संगठन, जनप्रतिनिधियों, पार्टी के पूर्व पदाधिकारियों और विचार परिवार के प्रतिनिधियों के साथ विभिन्न बैठकों में शामिल होंगी।



रायपुर पहुंचकर BJP कार्यालय में सुनी मन की बात

रायपुर पहुंचने के बाद स्मृति ईरानी भाजपा कार्यालय पहुंचीं। यहां उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, प्रदेश सह प्रभारी सिद्धार्थ शंभू, सांसद बृजमोहन अग्रवाल, राज्यसभा सांसद लक्ष्मी वर्मा सहित पार्टी के अन्य पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और आम लोगों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' को सुना। इस दौरान सभी लोग जमीन पर बैठकर कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके बाद पार्टी कार्यालय में संगठन से जुड़ी बैठकों का सिलसिला शुरू हुआ। प्रदेश प्रभारी के रूप में स्मृति ईरानी का यह दौरा संगठनात्मक गतिविधियों और आगामी राजनीतिक रणनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

स्मृति ईरानी का 2 दिवसीय दौरा

भाजपा की राष्ट्रीय महामंत्री एवं छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी स्मृति ईरानी अपने दो दिवसीय प्रवास पर रायपुर पहुंचीं। उनके इस दौरे को प्रदेश संगठन के साथ परिचय, संवाद और संगठनात्मक गतिविधियों की समीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

भाजपा प्रदेश कार्यालय में हुआ स्वागत

एयरपोर्ट से कुशाभाऊ ठाकरे परिसर पहुंचने पर स्मृति ईरानी का भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव सहित पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने स्वागत किया। इस दौरान प्रदेश संगठन के नेताओं और पदाधिकारियों ने उनसे मुलाकात की।

स्मृति ईरानी ने भी पार्टी के पदाधिकारियों से मुलाकात कर संवाद किया। प्रदेश प्रभारी के रूप में उनके

पहले दौरे के चलते प्रदेश भाजपा के संगठनात्मक कामकाज और आगामी गतिविधियों को लेकर इस प्रवास को अहम माना जा रहा है।

कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में स्वागत और मुलाकात के बाद उनके निर्धारित संगठनात्मक कार्यक्रमों पर सबकी नजर है। दौरे के दौरान प्रदेश संगठन के अलग-अलग स्तरों पर काम कर रहे नेताओं के साथ चर्चा का कार्यक्रम तय है। स्मृति ईरानी के प्रथम छत्तीसगढ़ आगमन पर राजधानी रायपुर में एयरपोर्ट से लेकर शहर की प्रमुख सड़कों तक भव्य स्वागत रैली निकालने की तैयारी की गई थी। हालांकि, प्रस्तावित भव्य रैली के बजाय उनके स्वागत कार्यक्रम को सादगीपूर्ण रखा गया। एयरपोर्ट पर स्वागत के बाद वह सीधे भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचीं, जहां पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया।



प्रदेश संगठन के साथ होगी महत्वपूर्ण बैठक

स्मृति ईरानी के दो दिवसीय प्रवास के दौरान प्रदेश भाजपा के संगठनात्मक ढांचे से जुड़े विभिन्न स्तरों के नेताओं के साथ बैठकें निर्धारित हैं। इनमें प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री (संगठन), प्रदेश महामंत्री और अन्य पदाधिकारी शामिल होंगे। इसके अलावा संभाग और जिला स्तर के प्रभारियों तथा जिला अध्यक्षों के साथ भी बैठक प्रस्तावित है। इन बैठकों के माध्यम से प्रदेश में पार्टी की संगठनात्मक गतिविधियों, कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय और आगामी रणनीति से जुड़े विषयों पर चर्चा होने की संभावना है। दौरे के पहले दिन पूर्व सांसदों, पूर्व विधायकों और पूर्व प्रदेश पदाधिकारियों के साथ भी संवाद निर्धारित है। वहीं, भाजपा कोर ग्रुप की बैठक भी इस प्रवास के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शामिल है। स्मृति ईरानी के प्रवास के दूसरे दिन प्रदेश के भाजपा विधायकों और सांसदों के साथ बैठकें प्रस्तावित हैं। इसके अलावा राज्य मंत्रिमंडल के मंत्रियों के साथ भी चर्चा की जाएगी। विभिन्न निगमों, मंडलों, आयोगों और बोर्डों के अध्यक्षों एवं उपाध्यक्षों के साथ समीक्षा बैठक का कार्यक्रम भी निर्धारित है। इसके साथ ही विचार परिवार के प्रमुख पदाधिकारियों और प्रतिनिधियों से भी संवाद किया जाएगा।

पहले दौरे से प्रदेश भाजपा को क्या संदेश

प्रदेश प्रभारी बनने के बाद स्मृति ईरानी का पहला छत्तीसगढ़ दौरा भाजपा संगठन के लिहाज से महत्वपूर्ण है। बैठकों में पार्टी के कामकाज की समीक्षा, विभिन्न स्तरों के नेताओं के बीच संवाद और आगामी राजनीतिक एवं संगठनात्मक प्राथमिकताओं पर चर्चा होने की संभावना। साथ ही दिवसीय प्रवास के दौरान होने वाली बैठकों के जरिए प्रदेश संगठन, जनप्रतिनिधियों और विचार परिवार के प्रतिनिधियों के साथ संवाद पर फोकस रहेगा।

बैठक में मंत्रियों के कामकाज पर सवाल

स्मृति ईरानी ने निगम-मंडल, बोर्ड और आयोगों के अध्यक्षों व उपाध्यक्षों के साथ बैठक की। इसके बाद पूर्व सांसदों और विधायकों की बैठक भी ली। बैठक में छत्तीसगढ़ में संगठन को मजबूत करने और सरकार की योजनाओं को घर-घर तक पहुंचाने पर चर्चा हुई। उन्होंने सत्ता और संगठन को एकजुट होकर काम करने के निर्देश दिए। संगठनात्मक कामकाज को आगे बढ़ाने के लिए जिला अध्यक्षों से बातचीत करने और निगम-मंडल के अध्यक्षों को दौरे करने के निर्देश दिए गए। मंत्रियों को अपने-अपने विभागों के कामकाज में सक्रियता बढ़ाने के लिए भी कहा गया। सांसदों और निगम-मंडल के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में मंत्रियों के खिलाफ सबसे ज्यादा शिकायतें सामने आने की बात कही जा रही है। बैठकों के बाद बीजेपी प्रदेश प्रभारी स्मृति ईरानी पार्टी कार्यालय से बिना प्रोटोकॉल के रवाना हुईं। उनके मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात करने की संभावना है।

मंत्री के काफिले को एंट्री नहीं, पुलिस सुरक्षा हटाई गई

बैठक में शामिल होने पहुंचे भाजपा कार्यालय के अंदर मंत्री खुशवंत साहेब के काफिले को भी एंट्री नहीं मिली। मंत्री गाड़ी से उतरे और पैदल प्रदेश कार्यालय पहुंचे। वहीं, स्मृति ईरानी के निर्देश पर बीजेपी कार्यालय के भीतर से पुलिस सुरक्षा भी हटाई गई थी। बता दें कि प्रदेश प्रभारी बनने के बाद स्मृति ईरानी का यह पहला छत्तीसगढ़ दौरा है। उनके स्वागत के लिए न तो एयरपोर्ट पर ढोल-ताशे बजाए गए और न ही किसी मंत्री को बुलाया गया।

कार्यकर्ता को सेल्फी लेने से रोका

वहीं, एक कार्यकर्ता स्मृति ईरानी के साथ सेल्फी लेना चाह रही थी। इस पर स्मृति ईरानी ने प्यार से उनके सिर पर हाथ रखा और सेल्फी लेने से मना कर दिया। स्मृति ईरानी के साथ प्रदेश सह-प्रभारी सिद्धार्थ शंभू भी छत्तीसगढ़ पहुंचे।

‘मन की बात’ देश की लोकशक्ति की आराधना और 140 करोड़ देशवासियों से आत्मीय संवाद का सशक्त माध्यम: मुख्यमंत्री



रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने रायपुर जिले के अभनपुर स्थित अग्रवाल भवन में पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी एवं श्री सिद्धार्थ शंभू के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय मासिक रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' की 139वीं कड़ी का श्रवण किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि 'मन की बात' देश की लोकशक्ति की आराधना और 140 करोड़ देशवासियों के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आत्मीय जुड़ाव का सशक्त

माध्यम है। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम के माध्यम से समाज, पर्यावरण, संस्कृति, नवाचार और जनसेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रहे सामान्य नागरिकों के असाधारण प्रयासों को राष्ट्रीय पहचान देते हैं। ऐसे प्रेरक उदाहरण देशवासियों में समाज और राष्ट्र के लिए कुछ नया करने का भाव जागृत करते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह प्रत्येक छत्तीसगढ़वासी के लिए गर्व का विषय है कि प्रधानमंत्री ने 'मन की बात' की

विभिन्न कड़ियों में प्रदेश की समृद्ध संस्कृति, जनजातीय परंपराओं, खेल प्रतिभाओं, जल संरक्षण, पोषण और नवाचार से जुड़े प्रयासों को प्रमुखता से स्थान दिया है। उन्होंने बस्तर ओलंपिक और बस्तर पंडुम का उल्लेख कर बस्तर की खेल प्रतिभाओं एवं समृद्ध जनजातीय संस्कृति को राष्ट्रीय पहचान दी है। आज शांति, विश्वास और विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा बस्तर अपनी युवा प्रतिभाओं और सांस्कृतिक विरासत के माध्यम से नई

पहचान बना रहा है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोरिया जिले में जल संरक्षण के अभिनव 'पांच प्रतिशत मॉडल' की भी सराहना की है, जिसके तहत किसान अपनी भूमि के पांच प्रतिशत हिस्से में तालाब बनाकर वर्षा जल का संचय करते हैं। इससे सिंचाई के साथ भूजल संरक्षण को भी बढ़ावा मिल रहा है। इसी प्रकार ऐतिहासिक मल्हार के ताम्रपत्रों और पोषण से जुड़े 'हर घर मुनगा' जैसे प्रयासों का उल्लेख

छत्तीसगढ़ की विशिष्ट पहचान को राष्ट्रीय मंच पर प्रतिष्ठित करता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'मन की बात' की 139वीं कड़ी में कार्यक्रम की 12 वर्षों की यात्रा का उल्लेख करते हुए देश के सामान्य नागरिकों के परिश्रम, सेवा और समर्पण की सराहना की। उन्होंने पंजाब में प्राकृतिक कपास की खेती और बुनकरी से महिला सशक्तिकरण, उत्तराखंड में हेवल नदी के पुनर्जीवन, स्थानीय उत्पादों की वैश्विक पहचान और खादी की बढ़ती लोकप्रियता जैसे प्रेरक प्रयासों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने त्योहारों के अवसर पर स्थानीय कारीगरों के उत्पादों को प्राथमिकता देने और 'वोकल फॉर लोकल' को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। उन्होंने ई-संजीवनी, आधुनिक अनुसंधान, युवाओं के डीप-टेक स्टार्टअप, श्रीअन्न की खेती और अंगदान के महत्व को भी रेखांकित किया। साथ ही सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती पर 'रन फॉर यूनिटी' में सहभागिता, स्वच्छता और सामाजिक एकता को मजबूत करने का संदेश दिया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री के विचार हमें अपने आसपास हो रहे सकारात्मक कार्यों से प्रेरणा लेने और समाज एवं राष्ट्र के प्रति अपने दायित्वों को पूरी निष्ठा से निभाने की प्रेरणा देते हैं। 'मन की बात' ने स्वच्छता, पर्यावरण एवं जल संरक्षण, स्थानीय उत्पादों के प्रोत्साहन, नवाचार, सेवा और जनभागीदारी को जन-जन से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।